Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-18, अंक-07 01-15 अप्रैल, 2023 (पाक्षिक) ₹20

'हमें विकास के पथ पर अग्रसर नया कर्नाटक बनाना है'

एक बार भाजपा, बार-बार भाजपा

चल्लेकेरे (कर्नाटक) में 17 मार्च, 2023 को एक रोड शो के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेतागण

समालखा पट्टी कल्याण (हरियाणा) में 19 मार्च, 2023 को 'शक्ति केंद्र समागम' को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 15 मार्च, 2023 को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

त्रिशूर (केरल) में 12 मार्च, 2023 को जनशक्ति रैली के दौरान जनाभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

19 मार्च, 2023 को जूनागढ़ जिला सहकारी बैंक मुख्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में 18 मार्च, 2023 को 350 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

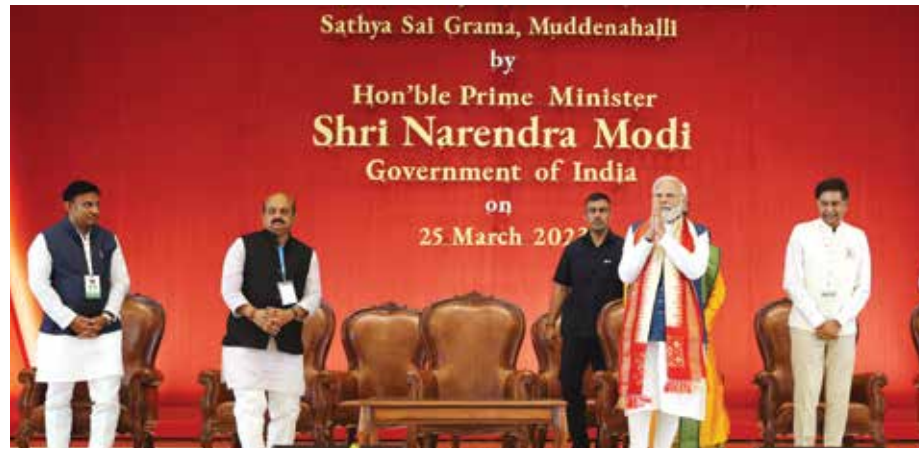

06 'सबका प्रयास' से भारत विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग पर: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 मार्च, 2023 को कर्नाटक का दौरा किया। श्री मोदी ने चिक्काबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन तथा एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो...

08 विजय संकल्प यात्रा, कर्नाटक

चल्लेकेरे में रोड शो के दौरान उमड़े विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा...

14 'सहकार समृद्धि सौध' का शिलान्यास

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 24 मार्च को बेंगलुरू, कर्नाटक में 'सहकार समृद्धि सौध' का...

32 जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर 20 मार्च को नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और विभिन्न...

33 प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मार्च को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा...

लेख

भारत को 'साइबर सुरक्षित समाज' क्यों बनना चाहिए / **अमित शाह** 20
भाजपा एवं भारत / **शिव प्रकाश** 22
'अमृतकाल' को ऊर्जावान बनाते / **हरदीप सिंह पुरी** 24
'भारत का युवा एक अनिश्चित दुनिया में भी आशान्वित है'/ **अनुराग सिंह ठाकुर** 28
'श्री अन्न'— किसानों के लिए वरदान / **राजकुमार चाहर** 30

अन्य

'राहुल गांधी देश-विरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं' 10
'क्या कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका को भी जेब में रखना चाहती है?' 12
'ये सिर्फ पार्टी कार्यालय नहीं, बल्कि संस्कार केंद्र हैं' 13
कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों की बात तो करती है, लेकिन उनके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करती : अमित शाह 14
सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.58 प्रतिशत बढ़कर हुआ 16.68 लाख करोड़ रुपये 15
मोदी स्टोरी 18
कमल पुष्प 18
ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन, नई दिल्ली 26
युवाओं से देश के पुनर्निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाने का आह्वान 27
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का किया उद्घाटन 31

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

भारत का मिलेट मिशन देश के उन ढाई करोड़ छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है, जो आजादी के दशकों बाद तक उपेक्षित रहे।

(18 मार्च, 2023)

जगत प्रकाश नड्डा

आज हरियाणा के समालखा में आयोजित शक्ति केंद्र संगम में उपस्थित शक्ति केंद्र प्रमुखों को संबोधित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में देश ऐतिहासिक उपलब्धियां व प्रतिष्ठा अर्जित कर रहा है। अंत्योदय व सेवा के संकल्प को भाजपा कार्यकर्ता जन-जन तक ले जाएंगे।

(19 मार्च, 2023)

अमित शाह

धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति प्रस्थापित हो रही है और घाटी व जम्मू एक बार पुनः पुरानी सभ्यता व परंपराओं की ओर लौट रहे हैं। मोदी सरकार यहां की संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए अनेक मंदिरों व आस्था-केन्द्रों का जीर्णोद्धार कर रही है।

(22 मार्च, 2023)

राजनाथ सिंह

आज लखनऊ में 350 से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विकास कार्यों को तेज़ी से पूरा करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जनता उत्तर प्रदेश को विकास की नई बुलंदियों की तरफ़ बढ़ते हुए देख रही है।

(18 मार्च, 2023)

बी.एल. संतोष

चुनाव तेजी से नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस आलाकमान अपने संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार श्री सिद्धारमैया के लिए एक सुरक्षित सीट तलाशने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहने वाले 17 उम्मीदवारों को देखते हुए कांग्रेस नहीं चाहती कि सिद्धारमैया का भी वही हाल न हो जो डॉ. जी. परमेश्वर का हुआ।

(19 मार्च, 2023)

डॉ. के. लक्ष्मण

मजदूरों को मिल रही है सामाजिक सुरक्षा! ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 28.64 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण पूरा किया जा चुका है। इन पंजीकृत श्रमिकों में 2.67 करोड़ घरेलू महिलाएं हैं।

(21 मार्च, 2023)

संपादकीय

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अक्षम्य कृत्य

जिस प्रकार से कांग्रेस एक अक्षम्य कृत्य का बचाव कर रही है, वह न केवल दुर्भाग्यजनक है, बल्कि भर्त्सनीय है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत रद्द हुई है, परंतु यह अत्यंत शर्मनाक है कि कांग्रेस इस निर्णय का विरोध कर रही है। जनप्रतिनिधि कानून, 1951 के धारा 8(3) के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दंड प्राप्त होने पर सदस्यता का स्वतः रद्द हो जाना कानूनी प्रावधान है। चूंकि न्यायालय एवं कानून ने अपना कार्य किया है, इसलिए अपील के माध्यम से राहत भी कानून के अंतर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कांग्रेस इस प्रकरण से राजनैतिक लाभ उठाना चाह रही है। राहुल गांधी के अयोग्य घोषित होने के विषय का राजनीतिकरण करने के प्रयास से कांग्रेस की आधारहीन-प्रोपगेंडा वाली राजनीति जनता के सामने बेनकाब हुई है। वो दिन बीत गए जब जनता कांग्रेस के झूठ एवं फरेब की राजनीति के झांसे में आती थी, अब तो जनता हर चुनाव में कांग्रेस को इसके लिए सबक सिखा रही है। हर कोई स्पष्ट देख सकता है कि राहुल गांधी को न्यायालय ने उनके गैर-जिम्मेदार, विभाजनकारी एवं गाली-गलौज की गिरी हुई राजनीति के कारण सजा दी है। देश किसी भी राजनैतिक दल के राष्ट्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार, सामाजिक रूप से स्वीकृत एवं गंभीरतापूर्ण वक्तव्य देते हुए देखना चाहता है, परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी राजनीति के स्तर को निरंतर इतना गिरा रहे हैं कि जनता उन्हें चुनावों में बार-बार धूल चटाना पसंद करती है।

> **राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत रद्द हुई है, परंतु यह अत्यंत शर्मनाक है कि कांग्रेस इस निर्णय का विरोध कर रही है**

राहुल गांधी के अयोग्य घोषित होने का विरोध कर कांग्रेस वही गलती कर रही है जो वह बार-बार दुहराती है। देश के संविधान, न्यायालय, संसद, चुनाव आयोग, ईवीएम और अन्य सम्मानित लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले कर कांग्रेस लगातार अपनी दुरवस्था के लिए आत्मचिंतन से बचती रही है। जब भी कोई न्यायालय इसके विरुद्ध निर्णय देता है, ये न्यायालय को कोसते हैं और जब चुनाव हारते हैं तब चुनाव आयोग फिर ईवीएम और यहां तक कि मतदाताओं तक को गाली देते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अब जबकि राहुल गांधी को न्यायालय ने दंडित किया है, इसके समर्थक कानून को ही गलत ठहरा रहे हैं। परन्तु विडंबना यह है कि इनमें से कोई भी राहुल गांधी को देश के पिछड़ा वर्ग को अपमानित करने वाली भाषा न बोलने की सलाह नहीं दे रहा है। परिणाम यह है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर यहां तक कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है तथा दूसरे देशों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं। जहां एक ओर वे भारत, जो 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में जाना जाता है, का अपमान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई चेतावनी के बाद भी वे उन्हीं गलतियों को दुहरा रहे हैं जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया है। देश को अब भी याद है कि किस प्रकार से 'चौकीदार चोर है' जैसे बयानों के लिए उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगनी पड़ी थी। आज, जब कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख लेने में असमर्थ है, यह झूठ, प्रोपगेंडा एवं फरेब की राजनीति कर रही है।

कांग्रेस का निरंतर पतन अब एक ऐसे दौर में इसे ले गया है जहां से इसका लौटना असंभव है। स्वतंत्रता के पश्चात् जिस प्रकार से इसका वैचारिक क्षरण शुरू हुआ, उसका परिणाम इसके संगठनात्मक बिखराव में हुआ। फलतः सत्ता-केंद्रित एवं सिद्धांतहीन राजनीति कांग्रेस के पतन का कारण बनी। आज यह राजनीति में हर प्रकार के दुर्गुण एवं बुराई की प्रतीक बनकर रह गई है। यह केवल वंशवादी राजनीति की अगुआ नहीं है, बल्कि वोट बैंक की राजनीति के कारण समाज को बांटने वाली जाति, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा और अन्य विखंडनकारी राजनीति की पर्याय बन गई है। आज जब जनता ने इसे सत्ता से बेदखल कर दिया है और हर चुनाव में सबक सीखा रही है, कांग्रेस दुष्प्रचार एवं झूठ की राजनीति का सहारा ले रही है। इसे लगता है कि बार-बार आधारहीन आरोपों को दुहराकर यह सत्ता में वापसी कर सकती है। जब तक यह रचनात्मक राजनीति से दूर रह लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान करती रहेगी तथा देश को तोड़ने वालों का समर्थन करेगी, जनता भी इसे चुनावों में धूल चटाती रहेगी। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

'सबका प्रयास' से भारत विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग पर: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 मार्च, 2023 को कर्नाटक का दौरा किया। श्री मोदी ने चिक्काबल्लापुर में श्री मधुसूदन साईं आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन तथा एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइटफील्ड (काडुगोडी) से कृष्णाराजपुरा मेट्रो लाइन का भी शुभारंभ किया और नई मेट्रो लाइन में सवारी की

जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि चिकबल्लापुर आधुनिक भारत के वास्तुकारों में से एक सर एम.एम. विश्वेश्वरैया की जन्मस्थली है। प्रधानमंत्री ने उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके संग्रहालय का दौरा करने का अवसर प्राप्त करने के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं इस पवित्र भूमि के सामने अपना सिर झुकाता हूं। श्री मोदी ने सत्य साईं ग्राम को सेवा का असाधारण मॉडल बताया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पहल के माध्यम से संस्था द्वारा चलाए जा रहे मिशन की सराहना की।

श्री मोदी ने अमृत काल में विकसित राष्ट्र बनने के देश के संकल्प और इतने कम समय में इतने बड़े संकल्प को पूर्ण करने के प्रति लोगों की जिजीविषा का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही उत्तर है— एक मजबूत, दृढ़ और साधन संपन्न उत्तर अर्थात् 'सबका प्रयास'। हर देशवासी के प्रयास से यह निश्चित रूप से साकार होने जा रहा है।

उन्होंने 'विकसित भारत' की उपलब्धि को हासिल करने की यात्रा में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका के साथ-साथ संतों, आश्रमों और मठों की महान परंपरा का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि यह सामाजिक और धार्मिक निकाय, आस्था और आध्यात्मिक पहलुओं के साथ गरीबों, दलितों, पिछड़ों तथा आदिवासियों को सशक्त बनाते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके संस्थान द्वारा किए गए कार्य 'सबका प्रयास' की भावना को मजबूत करते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश में 380 से कम मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज यह संख्या 650 से अधिक हो गई है। उन्होंने उल्लेख किया कि देश के आकांक्षी जिलों में 40 मेडिकल कॉलेज विकसित किए गए हैं जो कभी विकास के मामले में पिछड़ रहे थे। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल सीटों की संख्या दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में देश में चिकित्सकों की संख्या स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत में कुल चिकित्सकों की संख्या के समतुल्य होगी।

श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों की सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य माना है। हमने गरीबों और मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। उन्होंने जन औषधि केंद्रों या कम मूल्य औषधियों का उदाहरण देते हुए कहा कि आज देश भर में लगभग 10,000 जन औषधि केंद्र हैं, जिनमें से 1000 से अधिक कर्नाटक में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से गरीबों को दवाओं पर हजारों

प्रधानमंत्री ने बंगलौर मेट्रो की व्हाइटफील्ड से कृष्णाराजपुरा मेट्रो लाइन का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 मार्च को बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइटफील्ड (काडुगोडी) से कृष्णाराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने इसमें सवारी भी की।

करोड़ रुपये बचाने में मदद मिली है।

श्री मोदी ने अतीत का उल्लेख किया जब गरीब इलाज के लिए अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकते थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने गरीबों की इस चिंता पर ध्यान दिया और आयुष्मान भारत योजना के साथ इसका समाधान किया, जिसने गरीब परिवारों के लिए अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए हैं। श्री मोदी ने सर्जरी की महंगी प्रक्रियाओं, जैसे— दिल की सर्जरी, घुटने के प्रतिस्थापन और डायलिसिस आदि का उदाहरण दिया और जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने महंगी फीस को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

श्री मोदी ने स्तन कैंसर की ओर सरकार द्वारा दिए जा रहे विशेष ध्यान का उल्लेख करते हुए कहा कि गांवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं और शुरुआती दौर में ही ऐसी बीमारियों की जांच करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बोम्मई जी और उनकी टीम को राज्य में 9,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिए बधाई दी।

श्री मोदी ने एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को सक्षम तथा सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के 50 हजार एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं और लगभग 1 लाख पंजीकृत नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों को आधुनिक गैजेट्स प्राप्त हुए हैं तथा डबल इंजन सरकार उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

श्री मोदी ने कहा कि 'डबल इंजन' सरकार स्वास्थ्य के साथ-साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर भी पूरा ध्यान दे रही है। कर्नाटक को दूध और रेशम की भूमि बताते हुए प्रधानमंत्री ने पशुपालक किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से मवेशियों के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब देश स्वस्थ होगा और विकास के लिए 'सबका प्रयास' के प्रति समर्पित होगा, तब हम विकसित भारत के लक्ष्य को तेजी से हासिल कर सकेंगे।

इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, श्री सत्य साईं संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर के अध्यक्ष डॉ. सी. श्रीनिवास और सद्गुरु श्री मधुसूदन साई सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ■

प्रधानमंत्री ने हुबली-धारवाड़ में प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया

कर्नाटक की 'डबल इंजन' सरकार राज्य के हर जिले, गांव और कस्बे के संपूर्ण विकास के लिए प्रयासरत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मार्च को हुबली-धारवाड़, कर्नाटक में प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में आईआईटी धारवाड़ को राष्ट्र को समर्पित किया जाना शामिल है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने फरवरी, 2019 में किया था। इसके अलावा 1507 मीटर लंबे सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबली स्टेशन को भी समर्पित किया गया, जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है और इसे हाल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी मान्यता दी थी। साथ ही, क्षेत्र में संपर्क (कनेक्टिविटी) को बढ़ावा देने के लिए होसपेटे-हुबली-तीनाईघाट खंड के विद्युतीकरण और होसपेटे स्टेशन के उन्नयन कार्य का भी लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री ने हुबली-धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने जयदेव हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, धारवाड़ बहु-ग्राम जलापूर्ति योजना और तुपरिहल्ला फ्लड डैमेज कंट्रोल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक की डबल इंजन सरकार पूरी ईमानदारी के साथ राज्य के हर जिले, गांव और कस्बे के संपूर्ण विकास के लिए प्रयासरत है।

नया बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित

इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री ने अपनी मांड्या यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नया बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे कर्नाटक के सॉफ्टवेयर हब की पहचान को और आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी तरह श्री मोदी ने कहा कि बेलगावी में कई विकास परियोजनाओं को या तो समर्पित किया गया या उनकी आधारशिला रखी गई। उन्होंने शिवमोगा कुवेम्पु हवाई अड्डे का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि आज की परियोजनाओं के साथ-साथ ये परियोजनाएं कर्नाटक के विकास की एक नई कहानी लिख रही हैं। ■

विजय संकल्प यात्रा, कर्नाटक

हमें विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर नया कर्नाटक बनाना है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में चार विजय संकल्प रथयात्रा के माध्यम से 8,000 किमी की दूरी तय करते हुए प्रदेश के सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। इस दौरान जगह-जगह पर जनसभा, रोड शो और बाइक रैलियों का आयोजन किया जा रहा है और इसके माध्यम से राज्य की जनता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्ववाली 'डबल इंजन' सरकार की उपलब्धियों को साझा किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपने दो-दिवसीय कर्नाटक प्रवास के पहले दिन 17 मार्च, 2023 को चित्रदुर्ग, कर्नाटक के चल्लेकेरे में भाजपा की राज्यव्यापी विजय संकल्प यात्रा में भाग लिया और एक भव्य रोड शो किया। इसके पश्चात् वे चित्रदुर्ग में ही मोलकालमुरु में विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान वे मोलकालमुरु में मेगा बाइक रैली में शामिल हुए और एक भव्य रोड शो भी किया

चल्लेकेरे में रोड शो के दौरान उमड़े विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा की राज्यव्यापी विजय संकल्प यात्रा इस बात का संकल्प है कि हम सब लोगों को मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत बनाना है और विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर नया कर्नाटक बनाना है। यह कर्नाटक की विजय संकल्प यात्रा है न कि भाजपा की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम एक ऐसे कर्नाटक के निर्माण के लिए कृतसंकल्पित हैं जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, विकास से युक्त हो और जन-जन के जीवन में उत्थान का संवाहक हो। इसलिए हमारा नारा है— विकास, विकास और विकास। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारे वरिष्ठ नेता श्री बी.एस. येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई काफी अच्छे तरीके से कर्नाटक को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। हम सबको मिल कर इसमें योगदान देना है।

श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस मतलब परिवारवाद, जबकि भाजपा मतलब राष्ट्रवाद और विकासवाद। कांग्रेस ने देश को 'श्री C' अर्थात करप्शन, कमीशन और क्राइम की संस्कृति दी, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति प्रतिष्ठित की। कांग्रेस की नीति है भाई को भाई से लड़ाना, समाज को समाज से लड़ाना। यही उनकी विभाजनकारी नीति है जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीति है 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।'

उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियेपन की ओर जा रही है, वह निंदनीय भी है और दुःखदायी भी। कांग्रस पार्टी जो गतिविधि कर रही है और जो उनके नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, यह देश के लिए बहुत ही निंदनीय विषय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। अब तो हद हो गयी है। राहुल गांधी और कांग्रेस को भारत में कोई पूछता नहीं, उनकी कोई सुनता नहीं तो राहुल गांधी इंग्लैंड की सरजमीं पर जाकर कहते हैं कि भारत में प्रजातंत्र समाप्त हो गया है और अमेरिका तथा यूरोप को इसमें दखल देना चाहिए। राहुल

गांधीजी, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप चुनाव हार जाओ, तो इससे प्रजातंत्र खत्म नहीं होता। हमारे यहां कहावत है कि 'नाच न आवे आंगन टेढ़ा।' अगर हिंदुस्तान की जनता आप पर विश्वास नहीं करती तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव हुए। नागालैंड में कांग्रेस को 'जीरो' आया, त्रिपुरा में केवल तीन सीटें आईं और मेघालय में केवल पांच। राहुल गांधीजी, भारत में लोकतंत्र मजबूत है, समाप्त आपकी पार्टी हो गई है। आपको कोई नहीं पूछ रहा। इसलिए अनर्गल प्रलाप बंद कीजिये।

राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए श्री नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका और यूरोप से गुहार लगाते हैं कि भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करो। ऐसा कर राहुल गांधी भारत की संप्रभुता पर चोट कर रहे हैं, उसे चुनौती दे रहे हैं। जो भारत के संप्रभुता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करते हैं, ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टी को कर्नाटक की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से करारा सबक सिखाने का मन बना लिया है। राहुल गांधीजी, आपकी ही दादी की सरकार ने देश पर आपातकाल थोपकर लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया था। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने आपातकाल के दौरान सारे देश को जेलखाना बनाकर रख दिया था। ऐसे लोगों को घर में बिठाने का और भारतीय जनता पार्टी को पुनः सेवा का अवसर देने का कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी और जनता कहती है 'मोदी तेरा कमल खिलेगा।' कांग्रेस पार्टी के नेता आये दिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अपमान करते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्रीजी दिन-रात देश और कर्नाटक के विकास में लगे रहते हैं। कांग्रेस के नेता विदेशी सरजमीं पर जाकर भारत के खिलाफ भाषण देते हैं और भारत को कमजोर करने की बात करते हैं। दूसरे देशों को निमंत्रण देते है 'भारत में आओ'। ऐसा कर वे ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाना चाहते हैं क्या? राहुल गांधी विदेश में भारत की बुराई करते हैं जबकि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े से बड़े देश हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं। आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दे रहा है।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक में डबल इंजन वाली भाजपा सरकार में तेज गति से विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। कर्नाटक में जो हाईवे बने हैं, वह विकास का हाइवे है जो दर्शाता है कि कर्नाटक कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। ऐसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है जहां मैसूरु से बेंगलुरु तक अब केवल 75 मिनट में पहुंच जाएंगे। कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। यहां रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। शिवमोग्गा में एयरपोर्ट बना है। इसके साथ-साथ कर्नाटक में 11 एयरपोर्ट का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है। बेंगलुरु में एयरपोर्ट का टर्मिनल-II बना है जो देश में सबसे अत्याधुनिक है। नादप्रभु कैंपेगौड़ा जी की 108 फ़ीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। एफडीआई के तहत देश में सबसे अधिक निवेश कर्नाटक में हुआ है। कारोबार और उद्योग को सुविधा देने एवं उसे प्रोत्साहित करने के मामले में कर्नाटक पूरे देश में पहले स्थान पर काबिज है।

श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा विकास की गति को और तेज कर कर्नाटक की तस्वीर बदलने का संकल्प लेकर आई है। कांग्रेस और जेडीएस, दोनों ही परिवारवादी पार्टियां हैं। परिवारवादी पार्टियां कभी कर्नाटक का भला नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन वाली सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। ■

चार नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 23 मार्च, 2023 को ओडिशा, राजस्थान, बिहार एवं दिल्ली प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्षों की नियुक्ति की।

मनमोहन सामल | सी.पी. जोशी | सम्राट चौधरी | वीरेन्द्र सचदेवा

ओडिशा सरकार के पूर्व मंत्री श्री मनमोहन सामल को ओडिशा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा सांसद श्री सी.पी. जोशी को राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार विधान परिषद् सदस्य श्री सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है तथा दिल्ली प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा को दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी श्री अरुण सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपर्युक्त सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कांग्रेस नेता पर करारा प्रहार

'राहुल गांधी देश-विरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 मार्च, 2023 को प्रेस वक्तव्य जारी कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया और कहा कि मजबूत भारत, सशक्त लोकतंत्र और निर्णायक सरकार से भारत विरोधी लोगों को हमेशा से दिक्कत रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश-विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार-बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश-विरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं।

राहुल गांधी ने किया देश का अपमान

श्री नड्डा ने कहा कि एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है, उनके नेतृत्व में जहां जी-20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश की 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है?

उन्होंने कहा कि राहुल गांधीजी, आपने विदेशी धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र ख़त्म हो गया है और यूरोप-अमेरिका को इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की सम्प्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी क्या मंशा थी? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके क्या आप भारत की आर्थिक घेराबंदी और सामरिक घेराबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं?

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश के किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्यवाही करने का आह्वान नहीं किया है। राहुलजी, आपका यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता में भारी आक्रोश है। जन-प्रतिनिधियों में भी वही आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधीजी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी।

राहुल गांधीजी, आपने विदेशी धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र ख़त्म हो गया है और यूरोप-अमेरिका को इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की सम्प्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी क्या मंशा थी? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके क्या आप भारत की आर्थिक घेराबंदी और सामरिक घेराबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं

विदेशी मदद की मांग दुर्भाग्यपूर्ण

श्री नड्डा ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि मणिशंकर अय्यर का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाना और सलमान खुर्शीद का मोदीजी को हटाने में विदेशी मदद की मांग करना उनकी व्यक्तिगत सोच नहीं थी, बल्कि यह कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व की सोच है।

जिस इंग्लैण्ड ने हम पर वर्षों तक शासन किया, उसी सरजमीं पर जाकर राहुल गांधी स्वयं भारत में विदेशी ताकतों से दखल देने की मांग कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है?

उन्होंने कहा कि अब तो मुझे इस पर भी संदेह है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को कितना जानते हैं और कितना समझते हैं। अच्छा होता कि स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को यदि राहुल गांधी सही से पढ़ते तो उन्हें पता चलता कि लोकतंत्र की हत्या किसने की और लोकतंत्र की रक्षा किसने की।

कांग्रेस ने की लोकतंत्र की हत्या

श्री नड्डा ने कहा कि राहुलजी, आप आपातकाल के इतिहास को पढ़िए। आपकी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस देश में 19 महीनों तक आपातकाल लगाकर लगभग डेढ़ लाख बेगुनाह चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हों, युवा हों, वृद्ध हों, महिला हों— सबको अकारण जेल में डाल दिया था। तब बोलने पर प्रतिबंध, लिखने पर प्रतिबंध, मीडिया पर प्रतिबंध, फिल्मों पर प्रतिबंध, गायकों पर प्रतिबंध— न जाने, किन गुनाहों के लिए किस-किस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। राहुल गांधीजी, आपकी पार्टी ने तो देश की सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया ही, न्यायपालिका को भी कमजोर करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी थी। आपकी ही सरकारों ने लगभग 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को बेवजह बर्खास्त किया था। ये होती है लोकतंत्र की हत्या।

उन्होंने कहा कि राहुलजी, आपकी पार्टी के द्वारा जिस ढंग से आपातकाल को लगाकर देश के संविधान को समाप्त करने का प्रयास किया गया था, उसका प्रतिकार इसी देश की जनता ने किया और आपके शासन को उखाड़ फेंका। किसी विदेशी ताकत ने नहीं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधीजी, आप विदेशी धरती से भारत को बदनाम करते हैं जबकि आज दुनिया भारत को सलाम कर रही है। इटली की पीएम ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सबसे 'लवेबल पीएम' कहा। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने भारत की विकास गाथा की सराहना की है। जर्मनी के चांसलर ने भारत के विकास को अद्भुत बताया है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन, यूएई, सऊदी अरब सहित तमाम देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं। ये है राहुल गांधी की समझ।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का संघ है। जिसे राष्ट्र के रूप में 'भारत' में विश्वास ही नहीं, उसकी सोच पर क्या कहा जाय? राहुल गांधी जी, भारत 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' है जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र की शिक्षा दी। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।

उन्होंने कहा कि राहुल जी, आज आपकी और आपकी पार्टी की देश में कोई सुनता नहीं। देश की जनता आप पर विश्वास करती नहीं। यही कारण है कि आज आपकी पार्टी का देश से लगभग सफाया हो चुका है।

देश विरोधी टूलकिट गैंग की सक्रियता

श्री नड्डा ने कहा कि जब भी भारत में संसद सत्र शुरू होने वाला होता है, देश विरोधी टूलकिट गैंग अचानक से सक्रिय हो जाता है। कभी पेगासस की झूठी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, कभी आंदोलनों को भड़काया जाता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी कोई विदेशी अखबार की रिपोर्ट को लेकर हंगामा किया जाता है। कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नही बजती, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यहां एक हाथ तो सात समुद्र पार है और दूसरा यहां है और दोनों मिलकर ऐसी ताली बजाते हैं कि अपने देश को भी बदनाम करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता।

राहुल गांधीजी, आप विदेशी धरती से भारत को बदनाम करते हैं जबकि आज दुनिया भारत को सलाम कर रही है। इटली की पीएम ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सबसे 'लवेबल पीएम' कहा। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने भारत की विकास गाथा की सराहना की है। जर्मनी के चांसलर ने भारत के विकास को अद्भुत बताया है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन, यूएई, सऊदी अरब सहित तमाम देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं। ये है राहुल गांधी की समझ

उन्होंने कहा कि आखिर क्यों भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी है? आखिर क्यों चीन और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है? आखिर क्यों पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है? आखिर क्यों देश विरोधियों और कांग्रेस नेताओं की भाषा एक जैसी है?

कांग्रेस एवं तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स की मिलीभगत

श्री नड्डा ने कहा कि विदेशी ताकतें भारत में एक कमजोर और मजबूर गठबंधन की सरकार चाहती हैं, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने फायदे में सरकार का उपयोग कर सकें। भारत को कमजोर करना Deep State का षड्यंत्र है जिसमें कांग्रेस सहित तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स मिले हुए हैं, पर देश के करोड़ों-करोड़ों देशभक्त नागरिक कांग्रेस और विदेशी षड्यंत्रकारियों के इन मंसूबों को कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। ■

'क्या कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका को भी जेब में रखना चाहती है?'

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा देनेवाले सूरत सेशन कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठाए जाने पर प्रहार किया

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री रवि शंकर प्रसाद ने 23 मार्च, 2023 को प्रेस-वार्ता कर कहा कि सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानी मामले में 2 साल की सजा दी है। कांग्रेस के नेतागण इस मामले में बातें तो बहुत कर रहे हैं, किन्तु वे ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा था, जिसके कारण उन पर मानहानी का मुकदमा चला।

श्री प्रसाद ने कहा कि दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? आखिर राहुल गांधी के इस वक्तव्य का तात्पर्य क्या था? 'मोदी' सरनेम जाति सूचक शब्द है, 'मोदी' सरनेम वाले कई लोग खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, प्रोफेशनल, कारोबारी इत्यादि हैं। राहुल गांधी ने 'मोदी' सरनेम पर ऐसी बात कही, तो क्या उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?

उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी किसी खास सरनेम से जुड़े लोगों को इस तरह सार्वजनिक तौर पर अपमानित करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी होता है वह चोर होता है, तो मानहानि का मामला बिल्कुल बनता है। इस मामले में सूरत सेशन कोर्ट में बकायदा सुनवाई हुई और राहुल गांधी को भी अपना पक्ष रखने का भरपूर समुचित अवसर दिया गया।

उन्होंने कहा कि सूरत सेशन कोर्ट में पूरी सुनवाई के बाद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानी मामले में सजा सुनाई गयी है। दूसरी ओर, भाजपा नेता श्री सुशील कुमार मोदी ने भी सरनेम मामले को लेकर पटना में राहुल गांधी के खिलाफ एक केस दर्ज कर रखा है। उस मामले में भी राहुल गांधी बेल पर हैं।

श्री प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी बेहद आश्चर्यजनक लगती है, जब वे कहते हैं कि इस मामले में कोर्ट के न्यायधीश बार-बार बदले गए। इसका सीधा अर्थ है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देश की न्यायिक व्यवस्था पर भी भरोसा नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका को भी जेब में रखना चाहती है? खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अतः उन्हें जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। खड़गे जी द्वारा बार-बार न्यायाधीश बदलने वाला बयान देना अदालत की अवमानना है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में उत्तर-पूर्व में हुए चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। मिस्टर राहुल, सिर्फ इसलिए कि लोग आपको वोट नहीं देते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उन्हें दोष देने का अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको विदेशी धरती पर भारत और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों को बदनाम करने का लाइसेंस मिल गया है।

श्री प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा में विश्वास करता हूं। सत्य और अहिंसा में विश्वास करने का मतलब क्या विदेशी धरती पर जाकर अपने देश को गाली देना है? उन्होंने देश के प्रति कितनी भद्दी बातें पिछले दिनों कही थीं, वह सार्वजनिक है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश जाकर जाकर भारत को बदनाम करने देश के खिलाफ नफरत के बीज बोते रहे हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं, बल्कि राज्यों का संघ है। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी को भारत राष्ट्र के बारे में कितनी समझ है? दरअसल, यह एक माओवादी सोच है कि भारत कोई देश नहीं, बल्कि राज्यों का समूह है, जिसे संवैधानिक दबाव में एक रखा गया है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लन्दन में यह भी कहा कि भारत के लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। देश में लोकतंत्र की आवाज दबा दी गई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत हिंसक राज्य है। जबकि पिछले आठ सालों में जम्मू-कश्मीर में हिंसक घटनाओं में बहुत कमी आयी है। जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली का परिणाम है कि राहुल जी श्रीनगर में तिरंगा फहराकर आए।

श्री प्रसाद ने कहा कि लंदन में राहुल गांधी ने चीन की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा कि चीन सद्भावना से भरा देश है। 2022 में राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि भारत में मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया है, बस चिंगारी की जरूरत है। भारतीय विदेश सेवा की आलोचना करने में भी राहुल गांधी पीछे नहीं रहे। लंदन में पुलवामा हमले को महज कार धमाका करार देकर राहुल गांधी ने पुलवामा शहीदों का अपमान किया। ■

'ये सिर्फ पार्टी कार्यालय नहीं, बल्कि संस्कार केंद्र हैं'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10 मार्च, 2023 को तमिलनाडु के कृष्णागिरी में भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इससे पहले कभी भी 10 पार्टी कार्यालयों को एक साथ संचालित नहीं किया गया था।

श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कही बातों का उल्लेख करते हुए कहा कि 9 साल पूर्व 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आशा जतायी थी कि हर प्रदेश एवं हर जिला में पार्टी का कार्यालय बने। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अमित शाह ने उस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए योजनाएं बनाईं और इसका मिशन मोड पर क्रियान्वयन शुरू हुआ। भाजपा ने देश भर में 887 जिला पार्टी कार्यालय बनाने का फैसला किया है। अब तक भारतीय जनता पार्टी के 290 कार्यालय बन चुके हैं और उनका उद्घाटन भी हो चुका है। इस समय भाजपा के 517 जिला कार्यालय अपने निर्माण के अंतिम चरणों में है जबकि 115 जिला कार्यालय बनकर तैयार हैं और जल्द ही यहां कार्य संचालित होनेवाले हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में, 10 जिला कार्यालय भवनों ने आज से काम करने शुरु कर दिए हैं, 14 जिला कार्यालयों में पहले से ही कार्य संचालित हो रहे हैं जबकि 39 जिला कार्यालय यहां और निर्मित होनेवाले हैं।

उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कार्यालय नहीं, बल्कि संस्कार केंद्र हैं। इन संस्कार केंद्रों के माध्यम से एक कार्यकर्ता उन लक्ष्यों को समझता है जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है, और चुनाव के लिए उचित और कुशल रणनीति बनाना सीखता है। वह समझते हैं कि सही मायने में समाज और राष्ट्र के निर्माण में कैसे योगदान देना है। कार्यालय में होने वाली बातचीत और यहां श्रमिकों को दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यालय में कार्यकर्ता भाजपा की विचारधारा को सीखता है।

श्री नड्डा ने हाल ही में संपन्न उत्तर-पूर्व चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा कैसे लगातार आगे बढ़ रही है, इसे समझने के लिए नॉर्थ-ईस्ट के चुनाव परिणाम को देखना-समझना अत्यावश्यक है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार दोबारा सत्ता में आयी है। ईसाई बाहुल्य राज्य नागालैंड में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनी है। एनपीपी के अध्यक्ष और नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो के नेतृत्व में हम लोग दोबारा सत्ता में आए। मेघालय में सीएम कोनोर्ड संगमा को दुबारा हमने समर्थन दिया है। मेघालय भी ईसाई बाहुल्य राज्य है। इसलिए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र को भाजपा जमीनी धरातल पर साकार कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व मे नॉर्थ इस्ट के विकास एवं जनकल्याण के लिए बहुत सारे काम किए गए और वहां के एनडीए सरकार ने केन्द्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारा। श्री नड्डा ने कहा कि तमिलनाडु में भाजपा कार्यकर्ताओं के कठोर मेहनत से तमिलनाडु में आनेवाले समय में कमल खिलेगा, क्योंकि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विचारधारा पर आधारित है और कैडर बेस्ड पार्टी है। ■

तेलंगाना में एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत

17 मार्च, 2023 को घोषित परिणामों में तेलंगाना की महबूबनगर-रंगारेड्डी-हैदराबाद शिक्षक एमएलसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री एवीएन रेड्डी विजयी हुए। श्री रेड्डी ने 12,709 मतों की आवश्यक सीमा को पार करते हुए 13,436 मत हासिल किये। महबूबनगर-रंगारेड्डी-हैदराबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नौ जिले आते हैं, जिसमें लगभग 29,720 पंजीकृत मतदाता हैं। इस सीट के लिए 13 मार्च को मतदान हुआ। इस मतदान में 90.40 प्रतिशत वोट डाले गये।

श्री एवीएन रेड्डी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक ट्विटर संदेश में बधाई देते हुए कहा, "एमएलसी चुनावों में महबूबनगर-रंगारेड्डी-हैदराबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक जीत पर श्री एवीएन रेड्डी, बंदी संजय जी और तेलंगाना भाजपा इकाई को बधाई। लोगों ने एक बार फिर बीआरएस को त्याग कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के दृष्टिकोण को अपनाया है।" ■

विशाल जनशक्ति रैली, त्रिसूर (केरल)

कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों की बात तो करती है, लेकिन उनके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करती : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 12 मार्च, 2023 को त्रिसूर के वडक्कूमनाथन टेम्पल ग्राउंड में आयोजित एक विशाल जनशक्ति रैली को संबोधित किया।

भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने कम्युनिस्ट हिंसा में अपनी जान गंवाई हैं, श्रद्धांजलि देते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नाते मोदीजी 9 वर्षों से देश की सेवा करते आ रहे हैं। पिछले 70 सालों में देश में जितनी प्रगति नहीं हुई, उससे कहीं अधिक प्रगति विगत 9 सालों में हुई है। मोदीजी ने 2014 में जब देश का कार्यभार संभाला, उस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत 11वें स्थान पर था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदीजी के कुशल नेतृत्व में आज देश 5वें स्थान पर पहुंच गया है।

उन्होंने केरल की कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि केरल की जनता ने बहुत लंबे समय तक कम्युनिस्ट और कांग्रेस को बारी-बारी से शासन करने का मौका दिया है। कम्युनिस्ट को जहां पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है, वहीं पूरा देश कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है।

हाल ही में संपन्न त्रिपुरा विधानसभा का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि त्रिपुरा चुनाव के दौरान कांग्रेस और कम्युनिस्ट, दोनों पार्टियां आपस में इलू-इलू कर रहे थे, जबकि पूरे देश में ये दोनों पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपनी विचारधारा छोड़कर त्रिपुरा में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, किन्तु त्रिपुरा की जनता ने इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाते हुए भाजपा को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाया है।

वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा केरल को दी गयी सौगातों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि केन्द्र की यूपीए सरकार ने कर हस्तांतरण और विशेष सहायता ग्रांट दोनों मिलाकर केरल को 45,900 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पांच साल में 1.15 लाख करोड़ रुपये केरल को दिया है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी को इस राशि का हिसाब केरल की जनता को देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों की बात तो करती है, लेकिन उनके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करती। केंद्र की भाजपा सरकार ने केरल में 20 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में प्रति वर्ष 6-6 हजार रुपये भेजकर किसानों का सच्चा हितैषी बनकर दिखाया है। 'आयुष्मान भारत' के तहत 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक इलाज मुफ्त कराने का खर्च उठा रही है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 850 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष लागत से पूरे देश में मनरेगा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सर्वाधिक बजटीय आवंटन केरल को दिया गया है।

श्री शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने केरल के लिए सबसे बड़ा काम किया है कि हिंसा से त्रस्त केरल को मुक्ति दिलाने के लिए पीएफआई पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ■

'प्रधानमंत्री मोदी जी का यह लक्ष्य है कि पूरा देश समृद्ध बने'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 24 मार्च को बेंगलुरू, कर्नाटक में 'सहकार समृद्धि सौध' का शिलान्यास किया और कर्नाटक सरकार के सहकारिता विभाग के लगभग 1400 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज एस. बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा और कर्नाटक के सहकारिता मंत्री श्री एस.टी. सोमशेखर सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

श्री शाह ने अपने संबोधन में कहा कि सहकार समृद्धि सौध, कृषि व्यापार के लिए 67 एकड़ का बाजार यार्ड, बिनीपेट एपीएमसी में 11 करोड़ रुपये की लागत से फूल उत्पादकों के लिए बाजार, यशवंतपुरा एपीएमसी में 8 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी-लेवल कार पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 182 करोड़ रुपये की लागत से कुंभलगोडु, रामोहल्ली, जलाहल्ली, चिकनहल्ली, चुनचनाकुप्पे और कागलाहल्ली जैसी पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था की जा रही है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि पूरा देश समृद्ध और हर राज्य प्रगतिशील बने। ■

सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.58 प्रतिशत बढ़कर हुआ 16.68 लाख करोड़ रुपये

शुद्ध संग्रह 13.73 लाख करोड़ रुपये रहा; वर्ष-दर-वर्ष 16.78 प्रतिशत अधिक रहा। 2.95 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया; वर्ष-दर-वर्ष 59.44 प्रतिशत अधिक रहा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों में 10 मार्च, 2023 तक निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। 10 मार्च, 2023 तक का प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रदर्शित करता है कि सकल संग्रह 16.68 लाख करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की समान अवधि के सकल संग्रह से 22.58 प्रतिशत अधिक है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 13.73 लाख करोड़ रुपये रहा है जो पिछले वर्ष की समान अवधि के शुद्ध संग्रह की तुलना में 16.78 प्रतिशत अधिक है। यह संग्रह कुल बजट अनुमानों का 96.67 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल संशोधित अनुमानों का 83.19 प्रतिशत है।

जहां तक सकल राजस्व संग्रह के संदर्भ में कम्पनी आयकर (सीआईटी) और व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) की वृद्धि दर का सवाल है, सीआईटी के लिए विकास दर 18.08 प्रतिशत रही, जबकि पीआईटी (एसटीटी सहित) के लिए वृद्धि दर 27.57 प्रतिशत रही है। रिफंड के समायोजन के बाद सीआईटी संग्रह में शुद्ध वृद्धि 13.62 प्रतिशत और पीआईटी संग्रह में 20.73 प्रतिशत (केवल पीआईटी)/20.06 प्रतिशत (एसटीटी सहित पीआईटी) है।

1 अप्रैल, 2022 से 10 मार्च, 2023 के दौरान 2.95 लाख करोड़ रुपये की राशि के बराबर का रिफंड जारी किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 59.44 प्रतिशत अधिक है। ■

रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक के लिए 70,500 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को दी मंजूरी

भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति ईडब्ल्यू सिस्टम और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर-समुद्री से संबंधित 56,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद को मंजूरी दी गई, इसमें 99 फीसदी भारतीय उद्योगों से प्राप्त किया जाना है

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 16 मार्च, 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद् (डीएसी) की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में खरीदें- भारतीय आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) के तहत 70,500 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी अधिग्रहण के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) को मंजूरी प्रदान की है। इन कुल प्रस्तावों में से भारतीय नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव हैं। इनमें बड़े पैमाने पर स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (ईडब्ल्यू) प्रणाली, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर-मैरीटाइम आदि शामिल हैं।

ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की यह अतिरिक्त खरीद समुद्री हमले की क्षमताओं और एंटी-सरफेस वारफेयर ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी। वहीं, अतिरिक्त यूटीलिटी हेलीकाप्टर खोज व बचाव कार्यों, घायलों को बाहर निकालने, मानवीय सहायता आपदा राहत (एचएडीआर) आदि के क्षेत्र में भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता में बढ़ोतरी करेगा। इसी तरह, शक्ति ईडब्ल्यू प्रणाली दुश्मनों के किसी भी ऑपरेशनों से निपटने में नौसेना के अग्रिम पंक्ति के पोतों को सक्षम और आधुनिक बनाएगी।

मेक-I श्रेणी के तहत मध्यम गति समुद्री डीजल इंजन के लिए एओएन की मंजूरी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पहली बार भारत 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की दिशा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और उद्योगों की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए स्वदेशी रूप से ऐसे इंजनों के विकास और निर्माण का उद्यम कर रहा है।

केंद्र सरकार ने उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय रखने और पश्चिमी व उत्तरी मोर्चे पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए नए हथियारों की जरूरत और वितरण मंचों के साथ इसके एकीकरण की जरूरत महसूस की। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डीएसी ने लॉन्ग रेंज स्टैंड-ऑफ वेपन (एलआरएसओडब्ल्यू), जिसे एसयू-30 एमकेआई विमान पर स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और एकीकृत किया जाएगा, के लिए भारतीय वायु सेना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

आज के प्रस्तावों सहित वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत अधिग्रहण के लिए स्वीकृत कुल एओएन 2.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक के हैं, जिसमें से 99 फीसदी खरीद भारतीय उद्योगों से की जाएगी। इतनी बड़ी मात्रा में स्वदेशी खरीद भारतीय उद्योगों को 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करेगी। ■

अप्रैल-फरवरी 2022-23 के दौरान भारत के समग्र निर्यात में 16.18 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान

व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में अप्रैल-फरवरी 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि (अप्रैल-फरवरी 2021-22) की तुलना में 7.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सेवा निर्यात मजबूत बना हुआ है और अप्रैल-फरवरी 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि (अप्रैल-फरवरी 2021-22) की तुलना में 30.48 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 15 मार्च को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अप्रैल-फरवरी 2022-23 में भारत के समग्र व्यापार (वस्तु एवं सेवाओं को मिलाकर) में पिछले वर्ष (अप्रैल-फरवरी 2021-22) की समान अवधि की तुलना में 16.18 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है।

अप्रैल-फरवरी 2022-23 के दौरान व्यापारिक निर्यात अप्रैल-फरवरी 2021-22 की अवधि के दौरान हुए 377.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 405.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अप्रैल-फरवरी 2022-23 के दौरान गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न और आभूषण निर्यात 284.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ था, जबकि अप्रैल-फरवरी 2021-22 में यह 284.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा था। अप्रैल-फरवरी 2022-23 के लिए सेवाओं के निर्यात का अनुमानित मूल्य 296.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अप्रैल-फरवरी 2021-22 में यह 227.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

भारत का समग्र निर्यात (वस्तु एवं सेवा क्षेत्र को मिलाकर) फरवरी, 2023 में 63.02 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.81 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। फरवरी, 2023 में कुल आयात 65.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में (-) 4.38 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

फरवरी, 2023 के लिए सेवाओं के निर्यात का अनुमानित मूल्य 29.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि फरवरी, 2022 में यह 21.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। फरवरी, 2023 में गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न और आभूषण निर्यात 25.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ, जबकि फरवरी, 2022 में यह आंकड़ा 27.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। ■

थोक मुद्रास्फीति फरवरी, 2023 में दो साल के निचले स्तर 3.85 प्रतिशत पर

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति फरवरी, 2023 में घटकर दो साल से भी अधिक समय के निचले स्तर 3.85 प्रतिशत पर आ गई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 14 मार्च को एक बयान में कहा कि मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, गैर-खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों, खनिजों, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों, रसायन तथा रासायनिक उत्पादों, बिजली के उपकरणों और मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों की कीमतों में गिरावट के कारण हुई।

उल्लेखनीय है कि फरवरी, 2023 लगातार नौंवा महीना है जब थोक मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई। डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति जनवरी, 2023 में 4.73 प्रतिशत थी।

प्राथमिक वस्तुएं (भारांक 22.62 प्रतिशत)

इस प्रमुख समूह का सूचकांक फरवरी, 2023 में (-0.57 प्रतिशत) घटकर 173.0 प्रतिशत (अनंतिम) रह गया, जो जनवरी, 2023 के दौरान 174.0 (अनंतिम) था। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में जनवरी, 2023 की तुलना में फरवरी, 2023 में (0.45 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। जनवरी, 2023 की तुलना में फरवरी, 2023 में खनिजों (-1.37 प्रतिशत) और कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (-5.42 प्रतिशत) की कीमतों में गिरावट आई।

निर्मित उत्पाद (भारांक 64.23 प्रतिशत)

विनिर्मित उत्पादों के लिए 22 एनआईसी दो अंकों के समूहों में से 13 समूहों की कीमतों में वृद्धि देखी गई, जबकि 9 समूहों में कीमतों में कमी देखी गई। जनवरी, 2023 की तुलना में फरवरी, 2023 में कीमतों में कमी देखने वाले कुछ समूह हैं— खाद्य उत्पाद; कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑप्टिकल उत्पाद; रसायन और रासायनिक उत्पाद, विद्युत उपकरण और मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर आदि।

डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक (भारांक 24.38 प्रतिशत)

प्राथमिक वस्तु समूह से 'खाद्य वस्तुएं' और विनिर्मित उत्पादों से 'खाद्य उत्पादों' के मेल से बने खाद्य सूचकांक में जनवरी, 2023 के 171.2 से बढ़कर फरवरी, 2023 में 173.3 हो गया है। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक आधारित पर मुद्रास्फीति की दर जनवरी, 2023 के 2.95 प्रतिशत से घटकर फरवरी, 2023 में 2.76 प्रतिशत हो गई। ■

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ ग्राहकों को 8.15 प्रतिशत ब्याज दर की गई अनुशंसा

बोर्ड की अनुशंसा में लगभग 11 लाख करोड़ रुपये की कुल मूल राशि पर सदस्यों के खाते में 90,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण शामिल है। वितरित किए जाने के लिए अनुशंसित कुल आय अब तक की सर्वाधिक है

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में 28 मार्च को नई दिल्ली में ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 233वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष केंद्रीय श्रम और रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री श्री रामेश्वर तेली और सह-उपाध्यक्ष श्रम और रोजगार सचिव सुश्री आरती आहूजा और सदस्य सचिव, केंद्रीय पीएफ़ आयुक्त श्रीमती नीलम शमी राव भी उपस्थित थीं।

केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचयों पर 8.15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर जमा करने की अनुशंसा की। वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद सरकारी राजपत्र में ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा।

सीबीटी ने सुरक्षा उपायों के लिए विकास और अधिशेष निधि दोनों को संतुलित करने वाली राशि की अनुशंसा की। 8.15 प्रतिशत की अनुशंसित ब्याज दर अधिशेष की सुरक्षा के साथ-साथ सदस्यों की आय में वृद्धि की गारंटी देती है। वास्तव में 8.15 प्रतिशत की ब्याज दर और 663.91 करोड़ का अधिशेष पिछले वर्ष की ब्याज दर की तुलना में अधिक है।

बोर्ड की अनुशंसा में लगभग 11 लाख करोड़ रुपये की कुल मूल राशि पर सदस्यों के खाते में 90,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण शामिल है। वितरित किए जाने के लिए अनुशंसित कुल आय अब तक की सर्वाधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में आय और मूल राशि में वृद्धि क्रमशः 16 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से अधिक है।

ईपीएफओ पिछले कुछ वर्षों में न्यूनतम क्रेडिट जोखिम के साथ विभिन्न आर्थिक चक्रों के माध्यम से अपने सदस्यों को उच्च आय वितरित करने में सक्षम रहा है। ईपीएफओ निवेश के क्रेडिट प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ की ब्याज दर ग्राहकों के लिए उपलब्ध अन्य तुलनीय निवेश विकल्पों की तुलना में अधिक है। ईपीएफओ ने सावधानी और विकास के दृष्टिकोण के साथ मूलधन की सुरक्षा और संरक्षण पर सबसे अधिक बल देते हुए निवेश के प्रति युक्तिसंगत और संतुलित दृष्टिकोण का निरंतर पालन किया है।

सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठन में से एक होने के नाते ईपीएफओ इक्विटी और पूंजी बाजार में अस्थिरता की अवधि के दौरान भी अपने ग्राहकों को उच्च आश्वस्त ब्याज दर उपलब्ध कराने के द्वारा अपने उद्देश्य के प्रति सचेत रहा है। ■

जनवरी, 2023 के महीने में ईएसआई योजना के तहत जोड़े गए 16.27 लाख नए कर्मचारी

माह के दौरान जोड़े गए कुल 16.27 लाख कर्मचारियों में से 25 वर्ष तक की आयु वाले 7.52 लाख कर्मचारियों ने पंजीकरण कराया है। इससे पता चलता है कि देश के युवाओं को देश में रोजगार के अच्छे अवसर मिल रहे हैं

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अनंतिम पेरोल डेटा के अनुसार जनवरी, 2023 के महीने में 16.27 लाख नए कर्मचारियों को जोड़ा गया। पेरोल डेटा की साल-दर-साल तुलना से स्पष्ट होता है कि ऐसे 17.88 लाख कर्मचारियों की वृद्धि हुई है, जिन्होंने जनवरी, 2022 की तुलना में जनवरी, 2023 में ईएसआई योजना में योगदान दिया है।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 15 मार्च को जारी एक बयान के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत जनवरी, 2023 के महीने में लगभग 22,800 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए, जिसके माध्यम से उनके कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवर सुनिश्चित हुआ है।

माह के दौरान जोड़े गए कुल 16.27 लाख कर्मचारियों में से 25 वर्ष तक की आयु वाले 7.52 लाख कर्मचारियों ने पंजीकरण कराया है। इससे पता चलता है कि देश के युवाओं को देश में रोजगार के अच्छे अवसर मिल रहे हैं।

पेरोल डेटा के लिंग-वार विश्लेषण से संकेत मिलता है कि जनवरी, 2023 में केवल महिला सदस्यों का नामांकन 13.22 लाख रहा है। डेटा यह भी दर्शाता है कि जनवरी के महीने में कुल 44 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों ने ईएसआई योजना के तहत पंजीकरण कराया है। यह दिखाता है कि ईएसआईसी अपना लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ■

केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में पांच राज्यों को 1,816.162 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने 13 मार्च को 2022 के दौरान बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से प्रभावित पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर दी। यह इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले पांच राज्यों के लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

एचएलसी ने एनडीआरएफ से पांच राज्यों के लिए 1,816.162 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर की। अलग-अलग राज्यों को दी गई राशि का विवरण इस प्रकार है:

- **असम को 520.466 करोड़ रुपये**
- **हिमाचल प्रदेश को 239.31 करोड़ रुपये**
- **कर्नाटक को 941.04 करोड़ रुपये**
- **मेघालय को 47.326 करोड़ रुपये**
- **नागालैंड को 68.02 करोड़ रुपये**

यह अतिरिक्त सहायता केन्द्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में दी गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केन्द्र सरकार ने 25 राज्यों को उनके एसडीआरएफ में 15,770.40 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 4 राज्यों को 502.744 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

केन्द्र सरकार ने इन राज्यों में आपदाओं के तुरंत बाद उनसे ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीमों की प्रतिनियुक्ति कर दी थी। ■

बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के दो लगातार सफल उड़ान परीक्षण

अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 14 मार्च को ओडिशा के समुद्र तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर में बहुत कम दूरी की वायु प्रणाली (वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम– वीएसएचओआरएडीएस) मिसाइल से उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध एक भूमि (ग्राउंड)- आधारित मानव वहनीय प्रक्षेपक (मैन पोर्टेबल लांचर) से विमान के पास आने और उसके पीछे हटने की नकल करते हुए लगातार दो सफल उड़ान परीक्षण किए। मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा करते हुए इन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक रोका (इंटरसेप्ट किया) गया।

बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम– वीएसएचओआरएडीएस) एक मानव वहनीय वायु रक्षा प्रणाली (मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम – मैनपैड – एमएएनपीएडी) है जो कम दूरी पर रहने वाले एवं कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को निष्प्रभावी करने के लिए है। इसे डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से अनुसंधान केंद्र भवन, हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इस मिसाइल में डुअल-बैंड आईआईआर सीकर, मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सहित कई नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इसका प्रणोदन (प्रोपल्सन) एक दोहरी शक्ति वाली ठोस मोटर द्वारा प्रदान किया जाता है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एवं उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई तकनीकों से लैस यह मिसाइल सशस्त्र बलों को और अधिक तकनीकी बढ़त प्रदान करेगी। ■

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने की मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 17 मार्च को आईआरईडीए— नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के तहत एक सीपीएसई— को सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और नए इक्विटी शेयर जारी करके इरेडा हेतु धन जुटाने के लिए एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए मंजूरी दी।

यह निर्णय जून, 2017 में आईआरईडीए को आईपीओ के माध्यम से बुक बिल्डिंग आधार पर जनता के लिए 10.00 रुपये प्रत्येक के 13.90 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति देने के सीसीईए के पूर्व-निर्णय का स्थान ग्रहण करेगा। मार्च, 2022 में सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपये की पूंजी देने के बाद पूंजी संरचना में हुए बदलाव के कारण इस निर्णय की आवश्यकता हुई। ■

मोदी स्टोरी

हेडगेवार जयंती मनाने के लिए मोदी का अनूठा विचार

- नरेश शाह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अद्वितीय और अभिनव विचारों में एक साधारण घटना को विशेष घटना में बदलने की ताकत है। ऐसा ही एक आयोजन 1981-82 में गुड़ी पड़वा के अवसर पर हुई, जो रा.स्व.संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की जयंती भी है। गुजरात के स्वयंसेवक श्री नरेश शाह (गोपाल) बताते हैं कि कैसे इस उत्सव के लिए श्री मोदी का अनूठा विचार स्वयंसेवकों के लिए एक भावनात्मक क्षण बन गया।

रा.स्व.संघ छह त्यौहार मनाता है और ऐसा ही एक त्यौहार गुड़ी पड़वा है जो हिंदू कैलेंडर के पहले महीने का पहले दिन मनाया जाता है। यह डॉ. हेडगेवार की जयंती भी है। श्री शाह याद करते हैं कि श्री नरेन्द्र मोदी ने इस आयोजन के लिए एक अनोखे उत्सव का सुझाव दिया।

श्री नरेन्द्र मोदी ने सुझाव दिया कि जहां कार्यक्रम मनाया जा रहा है, वहां लाइट बंद करके हॉल में अंधेरा रखा जाए। इसके बाद उन्होंने पूरे कार्यक्रम में स्वयंसेवकों से मौन रहने को कहा। उनका विचार था कि हॉल में एकमात्र प्रकाश मंच पर डॉ. हेडगेवार की तस्वीर को रोशन करेगा। 1940 में डॉ. हेडगेवार के अंतिम भाषण की रिकॉर्डिंग का एक ऑडियो कैसेट उनके पास उपलब्ध था। श्री मोदी ने कहा कि यह ऑडियो रिकॉर्डिंग कार्यक्रम में चलाई जाएगी।

श्री शाह के अनुसार यह भाषण डॉ. हेडगेवार के 1940 के अंतिम भाषण की रिकॉर्डिंग मात्र थी, लेकिन वहां मौजूद स्वयंसेवकों को ऐसा लगा जैसे वे भाषण को लाइव सुन रहे हों। कार्यक्रम के दौरान पिन-ड्रॉप साइलेंस था और हॉल में डॉ. हेडगेवार की तस्वीर पर रोशनी के प्रभाव ने एक आभा पैदा की, जिससे स्वयंसेवकों को लगा जैसे डॉ. हेडगेवार उनके बीच ही हों। ऐसे आयोजन में शामिल होना स्वयंसेवकों के लिए एक भावनात्मक क्षण था और वे इस आयोजन से बहुत प्रेरित हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पास अपने शुरुआती दिनों से ही अभिनव विचारों के माध्यम से रा.स्व.संघ के कार्यक्रम आयोजित करने की दृष्टि थी। उनके सुझाव अक्सर एक साधारण कार्यक्रम को यादगार बना देते थे। उनकी यह कार्यशैली तब भी जारी रही, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने और अब भी जारी है जब वे इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ■

कमल पुष्प — सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

भाजपा की विचारधारा से अत्यंत प्रभावित

रेबती बिस्वास
प्रदेश अध्यक्ष
अंडमान एवं निकोबार

श्री रेबती बिस्वास का जन्म बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में हुआ था, लेकिन बाद में वे अंडमान के डिगलीपुर गांव चले गए। 21 वर्ष की छोटी सी उम्र में श्री बिस्वास गोपाल महाराज के शिष्य बन गए और अध्यात्मवाद के करीब पहुंच गए। श्री बिस्वास भाजपा की विचारधारा से अत्यंत प्रभावित थे और 1990 में श्री बिष्णु पद के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने अकेले दम पर देश के सबसे उत्तरी द्वीप दिगलीपुर में भाजपा की स्थापना की। दूर-दराज के इलाकों में जाकर उन्होंने लोगों को भाजपा के बारे में जागरूक किया और अंततः कई लोग भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक बन गए। 1996 में श्री बिस्वास के अथक प्रयासों से भाजपा के उम्मीदवार श्री बिष्णु पाड़ा को संसद सदस्य बनने में मदद मिली। 2013 में किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ी कि डिगलीपुर के किसानों को समय पर खाद मिले। इसके अलावा, उन्होंने साल भर सिंचाई प्रदान करने के लिए कलपोंग नदी पर एक बांध बनाने का सुझाव दिया। श्री रेबती विश्वास को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य का दायित्व भी दिया गया। 2005 में, वह डिगलीपुर ग्राम पंचायत के तहत पंचायत समिति के सदस्य के रूप में भी चुने गए, लेकिन उन्होंने इसके बजाय पार्टी के लिए काम करना पसंद किया। ■

भारत को 'साइबर सुरक्षित समाज' क्यों बनना चाहिए

अमित शाह

दुनिया ने पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तनों को देखा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग ने जीवन को सरल और तीव्र बना दिया है। लेकिन यह लाभ साइबर सुरक्षा से जुड़े कुछ गंभीर जोखिम के साथ आते हैं। साइबरस्पेस की सीमाहीन प्रकृति के साथ इससे जुड़े खतरे और साइबर अपराधियों के छलपूर्ण तरीके एवं उपकरण के कारण साइबर हमलों की प्रवृत्ति लगातार बदल रही है। इसके अलावा, आतंकवाद और कट्टरवाद को भी साइबर स्पेस में पनाह मिल रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "साइबर सुरक्षा अब डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया है।" साइबरस्पेस युद्ध का नया क्षेत्र बन गया है।

65 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता, 114 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ता, 6 लाख से अधिक गांवों तक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर और 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के डिजिटल लेनदेन के साथ भाजपा सरकार ने विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक सीमित सुविधाओं को जन-जन तक सफलतापूर्वक पहुंचाया है। डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के पीछे मूलभूत विचार यह था कि अगर गरीब की पहुंच प्रौद्योगिकी तक नहीं है, तो प्रौद्योगिकी को उन तक पहुंचना चाहिए

2014 से पहले यह माना जाता था कि डिजिटल सेवाओं तक पहुंच विशेष रूप से शहरी और समृद्ध परिवारों तक सीमित है। इस यथास्थितिवादी सोच से एक क्रांतिकारी बदलाव के साथ मोदी सरकार ने 2015 में प्रत्येक नागरिक के लिए 'मौलिक सेवा के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा' बनाने के लिए 'डिजिटल इंडिया' को एक व्यापक अवधारणा के रूप में पेश किया। 65 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता, 114 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ता, 6 लाख से अधिक गांवों तक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर और 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के डिजिटल लेनदेन के साथ भाजपा सरकार ने विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक सीमित सुविधाओं को जन-जन तक सफलतापूर्वक पहुंचाया है। डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के पीछे मूलभूत विचार यह था कि अगर गरीब की पहुंच प्रौद्योगिकी तक नहीं है, तो प्रौद्योगिकी को उन तक पहुंचना चाहिए।

तकनीकी प्रगति का मानवीय अनुप्रयोग हमेशा प्रधानमंत्री मोदीजी के लिए प्राथमिकता रहा है। उन्होंने प्रौद्योगिकी के उपयोग में संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए 'इमोशन ऑफ थिंग्स' को ध्यान में रखते हुए 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' पर काम करने पर लगातार जोर दिया है।

नौ वर्षों में हमारी सरकार ने खरीद, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ हस्तांतरण और वित्तीय समावेशन के लिए एक मजबूत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। मोदी सरकार के इन प्रयासों और पहलों ने अमृत काल की नींव रखी है - भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा।

लेकिन सरकार तकनीक के तेजी से विस्तार के साथ आने वाले खतरों के प्रति भी सचेत है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने और साइबर अपराध से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की एक परियोजना को पूरा किया गया है और पुलिस कांस्टेबल स्तर तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित किया

गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप केंद्रीय-राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय में काफी सुधार हुआ है, जिसमें एक समान साइबर रणनीति, साइबर अपराधों की रीयल-टाइम रिपोर्टिंग, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण, विश्लेषणात्मक उपकरणों का विकास, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क, साइबर स्वच्छता सुनिश्चित करना और नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक बनाना शामिल है।

क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) को अब देश के सभी 16,447 पुलिस थानों में एकीकृत कर दिया गया है। अब 99.9 प्रतिशत पुलिस थानों में 100 प्रतिशत एफआईआर तुरंत सीसीटीएनएस में दर्ज की जाती हैं। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) को अदालतों, पुलिस, अभियोजन पक्ष, जेलों और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के बीच डेटा का आदान-प्रदान करने और न्याय में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया है।

हाल ही में सरकार ने आईसीजेएस के दूसरे चरण को मंजूरी दी है, जो 'एक डेटा, एक प्रविष्टि' के सिद्धांत पर आधारित है और इसे हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के साथ एक समर्पित और सुरक्षित क्लाउड-आधारित बुनियादी ढांचे के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), जिसके तहत सात प्लेटफॉर्म; एक रिपोर्टिंग पोर्टल, एक साइबर-खतरा विश्लेषणात्मक इकाई, एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स और एक रिसर्च सेंटर हैं, यह एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करते हैं। अब तक पोर्टल पर 20 लाख से अधिक साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से 40,000 को एफआईआर में बदल दिया गया है। पंद्रह करोड़ लोगों ने इस पोर्टल का उपयोग किया है।

फिंगरप्रिंट डेटा सिस्टम 'NAFIS' को '1930 हेल्पलाइन' के साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें 300 करोड़ फिंगरप्रिंट डेटा स्टोरेज की क्षमता है। इस प्लेटफॉर्म पर 250 से अधिक बैंक और वित्तीय मध्यस्थ शामिल हैं, यह सिस्टम वास्तविक समय की कार्रवाइयों में मदद करता है जैसेकि धोखाधड़ी वाले धन को अवरुद्ध करना और ग्रहणाधिकार चिह्नित करना। टास्क फोर्स की त्वरित रिपोर्टिंग प्रणाली और कार्रवाई के परिणामस्वरूप अब तक 1.33 लाख से अधिक नागरिकों से साइबर अपराधियों द्वारा गबन किए गए 235 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई है।

गृह मंत्रालय सबसे कमजोर वर्ग को सुरक्षित बनाने के लिए साइबर स्वच्छता को बढ़ावा दे रहा है। हमारी सरकार ने हमेशा 'निवारक और सक्रिय दृष्टिकोण' के साथ अपनी जिम्मेदारी का पालन किया है - साइबर दुनिया के लिए फोरेंसिक-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को लगभग 100 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है

पोस्को (POCSO) के तहत दर्ज यौन उत्पीड़न के मामलों और इन मामलों की वास्तविक समय की निगरानी एवं प्रबंधन के लिए ITSSO (यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली) पोर्टल 2019 में लॉन्च किया गया था। सुरक्षित शहर परियोजना जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सशक्त वातावरण बनाना है, का विस्तार आठ चयनित शहरों में किया गया है।

गृह मंत्रालय सबसे कमजोर वर्ग को सुरक्षित बनाने के लिए साइबर स्वच्छता को बढ़ावा दे रहा है। हमारी सरकार ने हमेशा 'निवारक और सक्रिय दृष्टिकोण' के साथ अपनी जिम्मेदारी का पालन किया है - साइबर दुनिया के लिए फोरेंसिक-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को लगभग 100 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है।

साइबर सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्यों को उनकी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समर्थन देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। आई4सी के तहत 'CyTrain' पोर्टल पर एक विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म (MOOCs) को विकसित किया गया है, जबकि सेल कर्मचारियों को क्रिप्टो करेंसी, डार्क वेब, एनोनिमाइजेशन नेटवर्क, डीप फेक आदि पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।

साइबर सुरक्षा की चुनौतियां लगातार विकसित हो रही हैं और हमें खतरों से आगे रहने के लिए नए दृष्टिकोण 'नवाचार, अपनाना और लागू करना' को अपनाते रहना होगा। समाज एक प्रौद्योगिकी संचालित जीवन शैली की दिशा में विकसित हो रहा है। उपयुक्त नीति निर्धारित करने के लिए हमें सूक्ष्म पैमाने पर इस दीर्घकालिक बदलाव को समझना चाहिए— हमारा लक्ष्य 'साइबर सुरक्षित समाज' बनाना है न कि 'साइबर विफल समाज।'

हमें 'संवेदनशीलता के साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग' और 'सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने' के दोहरे उद्देश्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने का अवसर मिला है। हालांकि, यह कार्य अकेले सरकारों द्वारा नहीं किया जा सकता है। मैं नागरिकों से ऑनलाइन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जागरूक और सतर्क रहने की अपील करता हूं। साइबर सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि हमारी डिजिटल दुनिया सभी के लिए सुरक्षित बनें। ■

(लेखक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं)

भाजपा एवं भारत

शिव प्रकाश

देश में राष्ट्रवाद, गरीब कल्याण, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण, पारदर्शिता का आचरण करते हुए कांग्रेस के सम्मुख विकल्प प्रस्तुत करने के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। भारतीय राजनीति के मूर्धन्य विद्वान पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा 'एकात्म मानववाद' का वैचारिक आधार देकर जिसको पोषित करने का कार्य किया गया। अपने जन्म से सतत वृद्धि की ओर अग्रसर यह दल लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के समय जनता पार्टी में विलीन हो गया।

6 अप्रैल, 1980 को मुंबई सागर तट पर अटल गर्जना के साथ "अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा" के संकल्प के साथ भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाम से नए दल के रूप में प्रकट हुई। जिसका नेतृत्व भारतीय राजनीति के सूर्य 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी ने किया।

आज वही भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 18 करोड़ सदस्यता के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। केंद्र सहित देश के अनेक राज्यों में भाजपानीत सरकारें हैं। अपने राष्ट्रवादी विचार, गरीब के कल्याण की नीति, प्रखर एवं प्रामाणिक नेतृत्व के कारण देश के लिए वरदान सिद्ध हुई है।

राजनीति के माध्यम से राष्ट्रवाद की स्थापना करते हुए राष्ट्रीय एकात्मता को पुष्ट करने का विचार भाजपा ने अपने जन्मकाल से रखा। बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन तक लोकतंत्र का पालन करते हुए देश में लोकतंत्र का रक्षण भारतीय जनता पार्टी का संकल्प बना। समाज में बिना किसी भेदभाव के विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का पालन करते हुए गरीब का उत्थान यही लक्ष्य है। बिना किसी भेदभाव के अपनी-अपनी पूजा पद्धतियों का पालन करते हुए देश के विकास में सभी का सहयोग एवं 'देश प्रथम' सिद्धांत का पालन करते शुद्ध आचरण से देशवासियों की सेवा भाजपा का लक्ष्य बना।

राजनीति के माध्यम से राष्ट्रवाद की स्थापना करते हुए राष्ट्रीय एकात्मता को पुष्ट करने का विचार भाजपा ने अपने जन्मकाल से रखा। बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन तक लोकतंत्र का पालन करते हुए देश में लोकतंत्र का रक्षण भारतीय जनता पार्टी का संकल्प बना। समाज में बिना किसी भेदभाव के विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का पालन करते हुए गरीब का उत्थान यही लक्ष्य है। बिना किसी भेदभाव के अपनी-अपनी पूजा पद्धतियों का पालन करते हुए देश के विकास में सभी का सहयोग एवं 'देश प्रथम' सिद्धांत का पालन करते शुद्ध आचरण से देशवासियों की सेवा भाजपा का लक्ष्य बना

हमारा देश विविधताओं से युक्त देश है। भाषा, जाति, पूजा पद्धति, खानपान, रंग-रूप एवं पहनावा हम सबको एक-दूसरे से भिन्न दिखाते हैं। सतही तौर पर विचार करनेवाले एवं विदेशी षड्यंत्रों से प्रभावित अनेक लोगों ने इस विविधता को विभेद मानकर अपनी राजनीति का आधार बनाया। यह एक राष्ट्र नहीं, अपितु जातियों में परस्पर संघर्ष, आदिवासी-शहरवासी, सवर्ण-दलित आदि के आधार पर अपनी रोटियां एवं वोट की फसल काटने का प्रयास किया। भाजपा प्रारंभ से ही एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति के सिद्धांत के आधार पर राजनीति करती आई है। विविधता इसकी कमजोरी नहीं, इस देश का सौंदर्य है। उत्तर-पूर्वांचल ने भी भाजपा को चुनाव जिताकर इस स्वर को प्रकट किया है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि न तो अब उत्तर-पूर्वांचल दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। बंद, चक्का जाम, आतंक अब समाप्त होकर वहां विकास की धारा बह रही है। कश्मीर 370 से मुक्त होकर केसर की सुगंध ले रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अनूठी पहल 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के अंतर्गत काशी तमिल संगमम ने एकात्मता के विश्वास को गहरा दिया है। वेरूवाड़ी, कच्छ, कश्मीर के लिए संघर्ष करनेवाले भाजपा नेतृत्व ने राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय एकात्मता के भाव को जन-जन में जागृत किया है। इसी कारण देश के कोने-कोने से लेकर दुनिया के सुदूर स्थानों तक लाखों लोग देशभक्ति का समवेत स्वर 'भारत माता की जय' का उद्घोष कर रहे हैं।

देश के राजनीतिक धरातल पर सक्रिय दल अपने दल के अंदर का लोकतंत्र खोते जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया का पालन या तो है नहीं अथवा दिखावा मात्र है। कांग्रेस सहित देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवाद के संकट से ग्रसित है। इस कारण उन दलों का प्रतिभावान नेतृत्व कुंठित होकर दल छोड़ रहा है अथवा निष्क्रिय है। जो दल अपनी पार्टी में लोकतंत्र का पालन नहीं कर सकते

उनसे देश के लोकतंत्र की रक्षा की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। कांग्रेस ने तो देश पर आपातकाल थोपकर लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया ही है।

परिवारवाद के कारण देश का लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। यह आशंका अपने संविधान निर्माताओं के मन में भी थी। भाजपा ने अपने संविधान का पालन करते हुए निश्चित अवधि में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक की प्रक्रिया का पालन करते हुए देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। भाजपा ही एक मात्र ऐसा दल है जिसने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने दल का अस्तित्व समाप्त किया है।

लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान के इस व्यवहार ने भारतीय जनता के मन में भाजपा नेतृत्व के प्रति विश्वास को बढ़ाया है, जबकि अन्य दल चुनाव आयोग, ईवीएम एवं न्यायालय पर प्रश्नचिह्न ही खड़ा करने का कार्य कर रहे हैं।

गांधीजी अपने आर्थिक चिंतन में देश का विकास स्वदेशी एवं विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर चाहते थे। ग्राम पंचायत उनके स्वराज का आधार था। पं. दीनदयाल उपाध्याय ने सरकारों की सफलता का आधार गरीब कल्याण (अंत्योदय) को माना। स्वदेशी, सादगी, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था से हम अपनी आर्थिक उन्नति करें, यह विचार उन्होंने दिया। किसान के खेत को पानी, रोजगार; यह उनकी अर्थव्यवस्था के आधार थे। 'उत्पादन में वृद्धि, खर्च में संयम' यह सिद्धांत उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, नदियों को जोड़ने का प्रकल्प एवं सर्वशिक्षा अभियान; गरीब उत्थान एवं देश के ढांचागत विकास के अनुकरणीय उदाहरण हैं। उसी परंपरा में बहुगुणित वृद्धि करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी की गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं, क्रियान्वयन में तकनीकी उपयोग, कृषि सिंचाई योजना एवं आत्मनिर्भरता का मंत्र गांधीजी एवं दीनदयालजी की कल्पनाओं का साकार रूप है, जिससे गरीब का विश्वास अर्जित करते हुए देश आर्थिक क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़नेवाली अर्थव्यवस्था है।

तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारतीय संस्कृति एवं भारतीय समाज पर आक्रमण ही अनेक राजनीतिक दलों की परंपरा बन गई थी। जो जितनी अधिक एवं कठोर गाली देगा वह सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्षवादी हो गया था। भ्रष्टाचार में आंकठ डूबे नेता एवं दल अपने धर्मनिरपेक्षतावाद का आवरण ओढ़कर देशवासियों को शिक्षा दे रहे थे। जो हिंसा में लिप्त वह धर्मनिरपेक्ष होने का ढोंग रच रहे थे। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भगवान श्रीराम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। धर्मनिरपेक्षता तुष्टीकरण का पर्याय हो गई थी। समाज दुःखी मन से इन दलों के कारनामों को देख रहा था। भाजपा ने कहा कि हम विकास में कोई पक्षपात न करते हुए सभी को न्याय देंगे। अपने सांस्कृतिक मान बिंदुओं के गौरव के लिए भाजपा ने कदम से कदम मिला कार्य किया। आज भारत का सांस्कृतिक गौरव सूर्य के समान चमक रहा है। विश्व में चोरी करके ले जायी गयी मूर्तियों को वापिस लाने का कार्य हो अथवा श्रीराम मंदिर का भी कारिडोर, केदारनाथजी का सौंदर्यीकरण, महाकाल लोक का निर्माण; सभी अपनी गौरव गाथा कह रहे थे। सूफी संतों से संपर्क, बोहरा एवं पसमांदा मुस्लिम समाज के विकास की योजनाएं एवं वन डे वन चर्च जैसे प्रयास प्रधानमंत्री श्री मोदीजी के सर्वधर्म समभाव के भाव को प्रकट करते हैं।

2014 से पूर्व प्रतिदिन के समाचार-पत्रों में भ्रष्टाचार सुर्खियों में रहता था। राजनेता एवं राजनीतिक दल जैसे भ्रष्टाचार में आंकठ डूबे थे। सरकारी संपत्ति हमारे व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, जैसे सिद्धांत गढ़े जा रहे थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' का उद्घोष कर राजनीति में पारदर्शिता की मिसाल कायम की। 'देश प्रथम' के सिद्धांत का पालन करनेवाले अनेक राजनीतिक कार्यकर्ता भाजपा की देन है, जिन्होंने सत्ता के प्रतिष्ठान पर पहुंचकर भी अपनी ईमानदारी की छवि को बनाया है। राजनीति में सब कुछ जायज है, जहां यह सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता था, वहीं ईमानदारी से सरकार चलाई एवं पुनः बनाई जा सकती है, यह भाजपा नेतृत्व ने सिद्ध किया है। इसके कारण जीवन-मूल्य राजनीति में जीवित है। यह विश्वास जनता में जाग्रत हुआ है।

2014 से पूर्व प्रतिदिन के समाचार-पत्रों में भ्रष्टाचार सुर्खियों में रहता था। राजनेता एवं राजनीतिक दल जैसे भ्रष्टाचार में आंकठ डूबे थे। सरकारी संपत्ति हमारे व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, जैसे सिद्धांत गढ़े जा रहे थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' का उद्घोष कर राजनीति में पारदर्शिता की मिसाल कायम की

देश की स्वतंत्रता एवं विकास में सभी का योगदान है, इसके आधार पर सभी महापुरुषों का सम्मान, परमाणु विस्फोट एवं रक्षा क्षेत्र में आधुनिक सेना एवं शस्त्रों के द्वारा भारत को सम्मानित स्थान विश्व में भाजपा ने दिलाया है। विश्व भर में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता स्थापित की है। इसका परिणाम है, केवल भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व भारतीय जनता पार्टी को एवं उसके नेतृत्व को आशाभरी दृष्टि से देख रहा है। भाजपा भारत की आकांक्षाओं को पूर्ण करनेवाली पार्टी है जो अपने सेवाभाव से भारत के लिए वरदान सिद्ध होगी। ■

लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) हैं

'अमृतकाल' को ऊर्जावान बनाते

हरदीप सिंह पुरी

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक होने के कारण अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के साथ भारत 2020-2040 के बीच वैश्विक ऊर्जा मांग में लगभग 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखेगा, यह अनुमान बीपी एनर्जी आउटलुक और आईईए ने पेश किया है। इसलिए हमारी विशाल आबादी के लिए ऊर्जा तक पहुंच, उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। यह हमारे मामले को विशिष्ट बनाता है और हमारी ऊर्जा रणनीति को संचालित करता है, जिसे अब दुनिया भर में व्यावहारिक और संतुलित माना जाता है।

भारत ऐसा करने में कैसे कामयाब रहा है?

जब अमेरिका, कनाडा, स्पेन और ब्रिटेन में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 35-40 प्रतिशत तक बढ़ गईं, तब भारत जो अपने कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 85 प्रतिशत से अधिक और अपनी प्राकृतिक गैस आवश्यकताओं का 55 प्रतिशत आयात करता है, ने डीजल की घरेलू कीमतों में पिछले 1 साल में कमी देखी है। ऐसा उस समय में हुआ, जब हमारे पड़ोस के कई देशों में मांग को प्रबंधित करने के लिए 'ड्राईआउट' और बिजली की कटौती की गई है, लेकिन भारत में कहीं भी ईंधन की कमी नहीं हुई, यहां तक कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहे हैं।

यह ऊर्जा को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अपक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के कारण संभव हो पाया है। केंद्र और कई भाजपा शासित राज्यों ने उत्पाद शुल्क और वैट दरों में दो बार भारी कटौती की घोषणा की। इसके अतिरिक्त तेल पीएसयू ने भारी नुकसान को सहन किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का भार भारतीय उपभोक्ताओं पर न पड़े। हमारे पीएसयू द्वारा घरेलू गैस के कैप्टिव उपयोग को कम करने के बावजूद भी शहरी गैस वितरण क्षेत्र के लिए सब्सिडी वाली एपीएम गैस में भारी वृद्धि की गई। हमने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर निर्यात उपकर भी लगाया और घरेलू रूप से उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्याशित कर लगाया, ताकि रिफाइनर और उत्पादकों को घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में मुनाफाखोरी से रोका जा सके।

केंद्र और कई भाजपा शासित राज्यों ने उत्पाद शुल्क और वैट दरों में दो बार भारी कटौती की घोषणा की। इसके अतिरिक्त तेल पीएसयू ने भारी नुकसान को सहन किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का भार भारतीय उपभोक्ताओं पर न पड़े

इन वर्षों में भारत ने 27 देशों से 39 देशों तक कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ताओं के अपने नेटवर्क का विस्तार किया है। भारत ने कच्चे तेल की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका (पिछले चार वर्षों में ऊर्जा व्यापार 13 गुना बढ़ गया है) और रूस जैसे देशों के साथ संबंधों को और मजबूत किया है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आयातक के रूप में इस रणनीति ने न केवल भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित की, बल्कि वैश्विक पेट्रोलियम बाजारों पर भी इसका प्रभाव पड़ा।

जो अपरिहार्य है वह यह है कि भारत द्वारा कुछ देशों से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद ने वास्तव में वैश्विक मांग और लगभग 98-100 मिलियन बैरल/दिन की आपूर्ति को संतुलित रखा है, जिसने वैश्विक मूल्य श्रृंखला में तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखा है। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो वैश्विक कीमतें 300 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई होतीं।

हम पारंपरिक ईंधन अन्वेषण और ऊर्जा परिवर्तन दोनों पर काम कर रहे हैं। भारत को एक आकर्षक ऊर्जा गंतव्य बनाने में हमारे सुधार परामर्श फर्म 'वुड मैकेंज़ी' द्वारा अनुमोदित किये गये है, जो कहती है कि भारत 2023 का लाइसेंसिंग वाइल्डकार्ड हो सकता है। 2025 तक भारत अपने शुद्ध भौगोलिक अन्वेषण क्षेत्र को 8 प्रतिशत (0.25 मिलियन वर्ग किमी) से बढ़ाकर 15 प्रतिशत (0.5 मिलियन वर्ग किमी) करना चाहता है। इसने हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में निषिद्ध/नो-गो क्षेत्रों को 99 प्रतिशत तक कम कर दिया है, जिससे अन्वेषण के लिए लगभग 1 मिलियन वर्ग किमी को मुक्त किया गया है।

हालांकि, जैसा कि ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम अपनी जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं पर दृढ़ बने हुए हैं - 2070 तक शून्य उत्सर्जन और 2030 के अंत तक उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना।

हम जीवन स्तर में सुधार और तेजी से होने वाले शहरीकरण के अनुरूप अपने पेट्रोकेमिकल उत्पादन का भी विस्तार कर रहे हैं। भारत पेट्रोलियम उत्पादों का वैश्विक निर्यातक है और इसकी शोधन क्षमता अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया में चौथी सबसे बड़ी है। 2040 तक इस क्षमता को 450 एमएमटी तक बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। रिफाइनिंग क्षमता विस्तार भी पिछले साल अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान ईंधन की कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक था।

भारत 2030 तक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करके गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के अपने प्रयासों को भी तेज कर रहा है। भारत ने पिछले नौ वर्षों में 9.5 करोड़ से अधिक परिवारों को खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन से जोड़ा है। पीएनजी कनेक्शन 2014 में 22.28 लाख से बढ़कर 2023 में 1 करोड़ से अधिक हो गये हैं। भारत में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 2014 में 938 से बढ़कर 2023 में 4,900 हो गई है। 2014 से भारत ने अपने गैस पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई 14,700 किमी से बढ़ाकर 2023 में 22,000 किमी कर दिया है।

हाल ही में समाप्त हुए इंडिया एनर्जी वीक 2023 में भारत ने 'ई20' यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित गैसोलीन लॉन्च करके अपनी जैव ईंधन क्रांति में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसे अगले दो वर्षों में देश भर के 15 शहरों में शुरू किया जाएगा। भारत का इथेनॉल सम्मिश्रण गैसोलीन 2013-14 में 1.53 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 10.17 प्रतिशत हो गया है और अब भारत पांच दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र भी स्थापित कर रहा है जो कृषि अपशिष्ट को जैव ईंधन में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में और कमी आएगी और किसानों के लिए आय के अवसर पैदा होंगे।

देश में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और 4 मीट्रिक टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन की दिशा में भारत के प्रयासों में तेजी लाने के लिए 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। यह 2030 तक संचयी जीवाश्म ईंधन आयात में 1 लाख करोड़ रुपये बचाएगा। भारत 2030 तक हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए पूरी क्षमता के साथ तैयार है।

अपनी ऊर्जा रणनीति की तरह हम भी भारत के भविष्य के मोबिलिटी पाथवे को बदलने के लिए एक एकीकृत रास्ता अपना रहे हैं। इसलिए, हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन के साथ भारत 50 गीगावाट घंटे के उन्नत ईंधन सेल बनाने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों का भी समर्थन कर रहा है। इस क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क में छूट की भी घोषणा की गई है। हम मई, 2024 तक 22,000 खुदरा दुकानों पर वैकल्पिक ईंधन स्टेशनों (ईवी चार्जिंग/सीएनजी/एलपीजी/एलएनजी/सीबीजी) की स्थापना का लक्ष्य बना रहे हैं।

जैसाकि हम 2047 तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की अपनी अमृत काल योजना को लागू कर रहे हैं, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा प्रमुख लक्ष्य बना हुआ है। ■

(लेखक केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं)

केंद्रीय कृषि मंत्री ने डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल 'डिजीक्लेम' का किया शुभारंभ

इस नवाचार के साथ ही दावों का वितरण अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिसका सीधा लाभ प्रारंभ में 6 राज्यों (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व हरियाणा) के संबंधित किसानों को होगा

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल 'डिजीक्लेम' का 23 मार्च को शुभारंभ किया। इस नवाचार के साथ ही दावों का वितरण अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिसका सीधा लाभ प्रारंभ में 6 राज्यों (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व हरियाणा) के संबंधित किसानों को होगा।

दावा भुगतान की प्रक्रिया अब स्वचालित हो जाएगी, क्योंकि राज्यों द्वारा पोर्टल पर उपज डेटा जारी किया जाता है। श्री तोमर ने बटन दबाकर इन 6 राज्यों के बीमित किसानों को 1260.35 करोड़ रु. के बीमा दावों का भुगतान किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पीएमएफबीवाई का शुभारंभ 6 साल पहले किया गया था और उनकी मंशा है कि अधिकाधिक किसानों को इसका लाभ मिलें।

कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि डिजीक्लेम के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नई विधा का शुभारंभ हुआ, जिससे केंद्र-राज्य सरकारों को सुविधा के साथ ही किसानों को क्लेम मिल जाएं, इसकी सुनिश्चितता पारदर्शिता के साथ की जा सकेगी। 'आयुष्मान भारत योजना' के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत की बहुत बड़ी योजना है जो प्राकृतिक परिस्थितियों पर आधारित है। पिछले 6 साल से संचालित इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को उनकी उपज के नुकसान की भरपाई के रूप में अभी तक 1.32 लाख करोड़ रु. का भुगतान किया गया है। ■

ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन वैश्विक भलाई के प्रति भारत की जिम्मेदारियों का प्रतीक है: नरेन्द्र मोदी

भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उत्सव को एक 'जन आंदोलन' बनाने और भारत को 'मिलेट का वैश्विक केंद्र' के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, किसान, स्टार्ट-अप, निर्यातक, किसान, उपभोक्ता और जलवायु के लिए मिलेट (श्री अन्न) के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रचार करने के लिए खुदरा व्यवसायों और अन्य हितधारकों को लगाया जा रहा है। भारत में ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन का आयोजन इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 मार्च को नई दिल्ली में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर के सुब्रमण्यम हॉल में ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। इसके बाद श्री मोदी ने भारतीय मिलेट (श्री अन्न) स्टार्ट-अप कॉम्पेंडियम का शुभारंभ किया और बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स का डिजिटल तरीके से विमोचन किया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने अपने संदेश भी दिए।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन के आयोजन पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल वैश्विक भलाई के लिए एक आवश्यकता हैं, बल्कि वैश्विक भलाई के प्रति भारत की जिम्मेदारियों का प्रतीक भी हैं।

उन्होंने कहा कि लगभग 2.5 करोड़ छोटे किसान भारत में मिलेट्स के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। श्री मोदी ने कहा कि मिलेट्स, मानव और मिट्टी, दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलेट्स की एक और ताकत पर जोर देना चाहता हूं। मिलेट्स की यह ताकत है— इसका क्लाइमेट रेसिलियंट होना। श्री मोदी ने कहा कि भारत का मिलेट मिशन— श्री अन्न का अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होगा। ■

प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें

- अब श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है
- प्रति व्यक्ति प्रति माह श्री अन्न की घरेलू खपत 3 किलोग्राम से बढ़कर 14 किलोग्राम हो गई है
- भारत का श्री अन्न मिशन देश के 2.5 करोड़ बाजरा उत्पादक किसानों के लिए वरदान साबित होगा
- भारत ने हमेशा विश्व के प्रति उत्तरदायित्व और मानवता की सेवा के संकल्प को प्राथमिकता दी है
- एक तरफ फूड सिक्योरिटी की समस्या, तो दूसरी तरफ फूड हैबिट्स की परेशानी; लेकिन श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं
- भारत अपनी विरासत से प्रेरणा लेता है, समाज में परिवर्तन लाता है और इसे वैश्विक कल्याण के सामने लाता है
- श्री अन्न अपने साथ अनंत संभावनाएं लाते हैं

ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन में विभिन्न देशों के कृषि मंत्रियों की हुई गोलमेज कांफ्रेंस

ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन में दिल्ली आए विभिन्न देशों के कृषि मंत्रियों की 18 मार्च को गोलमेज कांफ्रेंस हुई। इसमें मेजबानी करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व में श्री अन्न को बढ़ावा देने का एजेंडा निर्धारित किया है। श्री अन्न भविष्य के सुपर फूड हैं और भूख, कुपोषण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में बहुत उपयोगी है।

कांफ्रेंस में मारीशस, गुयाना, श्रीलंका, सूडान, जाम्बिया व सूरीनाम के कृषि मंत्रियों तथा मालदीव, गाम्बिया व नाइजीरिया के उच्चाधिकारियों ने मिलेट्स के उत्पादन, खपत और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने में अपने-अपने देशों के अनुभव को साझा किया। ये सभी देश मिलेट्स उत्पादक प्रमुख देशों के बीच अधिक घनिष्ठ संबंध के पक्षधर हैं। विचार-विमर्श के दौरान मिलेट्स के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। ■

युवाओं से देश के पुनर्निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाने का आह्वान

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 मार्च, 2023 को एसआरएम यूनिवर्सिटी, चेन्नई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद को वर्चुअली संबोधित कर युवाओं से देश के पुनर्निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या, तमिलनाडु के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री के अन्नामलाई, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुघ और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. विनय सहस्रबुद्धे भी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इंग्लैंड में दिए गए भारत विरोधी बयान पर करारा हमला किया और कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी सरजमीं पर देश विरोधी बयान देकर मर्यादा की हर सीमा को लांघ दिया है। कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियेपन की शिकार हो गई है। ऐसे लोगों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है और ऐसे लोगों को प्रजातांत्रिक तरीके से छुट्टी कर देनी चाहिए।

श्री नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र की जननी भारत को विदेशी धरती पर बदनाम और निंदा करते हैं। साथ ही, राहुल गांधी विदेशी ताकतों को भी उकसा रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र अर्थात् देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप करें। भारत की जनता राहुल गांधी के शब्दों को सिर्फ सुनती नहीं है, बल्कि सहन कर रही है। जिनका देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वैसे लोगों को प्रजातांत्रिक तरीके से छुट्टी कर देने की जरूरत है।

भारतीय संस्कृति के धरोहर को समझते हुए देश के भविष्य में योगदान करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज भारत में असीमित अवसर है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि हमें एक युवा संसद के माध्यम से अनुभवी राजनीति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपने युवाओं को हर जानकारी देने की जरूरत है, ताकि वे देश के ज्वलंत मुद्दे पर सार्थक चर्चा करें। ■

महिला मोर्चा ने किया 'कमल मित्र' प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

भारतीय जनता महिला मोर्चा ने 11 मार्च, 2023 को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में महिला केंद्रित योजनाओं पर एकदिवसीय 'कमल मित्र' प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में प्रोफेसर, वकील, रिसर्च स्कॉलर्स, आईटी प्रोफेशनल्स समेत महिला प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया। यह महिला पेशेवरों के रिसोर्स पर्सन का समूह हैं, जो योजनाओं पर सत्र लेंगी और देश भर में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगी। कार्यशाला का उद्घाटन महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य सभा सदस्य सुश्री सरोज पाण्डेय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानथी श्रीनिवासन ने किया।

श्री सरोज पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में केंद्रीय योजना की महिला लाभार्थी है, लेकिन वे आधी आबादी है, फिर भी हमारे पास केंद्रीय योजनाओं का लाभार्थी बनाने के लिए एक बड़ी आबादी है।

महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानथी श्रीनिवासन ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि महिला मोर्चा कार्यकर्ता ने आनेवाले संसदीय चुनावों के लिए कमर कस ली है, हमने अपना रोडमैप तैयार कर लिया है। महिला मोर्चा हर महीने कार्यक्रम करेगा और साथ ही, हम अपने कार्यकर्ताओं को 'कमल मित्र' के रूप में प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इस देश की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस अभियान के माध्यम से हम प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 1 लाख 'कमल मित्र' बनाने जा रहे हैं, जो देश की महिलाओं को योजनाओं को दिलाने में मदद करेगी।

समापन सत्र को राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती अलका गुर्जर ने संबोधित किया। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी महिला सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, पीएमईजीपी योजना महिला सम्मान बचत योजना इन सभी योजनाओं से पता चलता है कि सभी वर्ग और आयु समूहों को सशक्तीकरण में लक्षित किया गया है। इस कार्यशाला में 33 राज्यों से 55 प्रतिभागी, 43 रिसोर्स पर्सन एवं 10 राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ■

'भारत का युवा एक अनिश्चित दुनिया में भी आशान्वित है'

अनुराग सिंह ठाकुर

दुनिया भर में युवा प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर विज्ञान, खेल, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय, राजनीति, रचनात्मकता, पर्यावरणीय स्थिरता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रगति कर रहे हैं, हालांकि इसमें व्यापक आर्थिक समस्याएं और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं कुछ बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन ये युवा वैश्विक सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के स्थानीय समाधान निकाल रहे हैं।

कोई भी दूरी, अंतर और सीमा वैश्विक स्तर पर युवाओं को सामाजिक परिवर्तन लाने से रोका नहीं पाती है और फॉर्च्यून 500 कंपनियां इस वेग की ओर इशारा करती हैं।

अर्जेंटीना में युवा फुटबॉल को गंभीरता से लेते हैं, स्वीडन और नॉर्डिक देशों में वे जलवायु परिवर्तन के बारे में मुखर हैं। संस्कृति और सामाजिक मूल्यों का नेतृत्व भारतीय स्टार्टअप कर रहे हैं। हितधारकों और कल के निर्माताओं के रूप में युवा जोश की शक्ति और जीवंतता बेजोड़ है। वे स्वयं के भविष्य का निर्माण करेंगे, तो दुनिया के लिए भी यह अनिवार्य है कि वे उनकी बातों पर ध्यान दें और उनकी भावनाओं, ऊर्जा और कार्यों को दिशा देने के लिए एक सार्थक मंच प्रदान करें।

भारत, मानवता के 1/6 हिस्से का घर है, जो विविधता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और मांग आधारित सिद्धांतों पर टिकी है— जिसे आध्यात्मिकता, खेल, सॉफ्टवेयर, स्थिरता, स्टार्टअप और सामाजिक उद्यमिता की भूमि के रूप में जाना जाता है। कुल आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा यानी भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश तेजी से सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और तकनीकी नवाचार के युग में प्रवेश करने के लिए तैयार है। चाहे सोशल मीडिया के नेतृत्व वाले सामाजिक परिवर्तन हों या अरबों डॉलर के स्टार्टअप, भारत के युवा आगे बढ़कर इनका हिस्सा बन रहे हैं।

बुद्ध की भूमि ने हमें ध्यान और आध्यात्मिकता सिखाई है। अपने 2014 यूएनजीए के भाषण में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा पेश किये गये योग दिवस के प्रस्ताव को 177 सदस्य राष्ट्रों द्वारा समर्थित किया गया था। दुनिया ने 21 जून, 2015 को अपना पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। 'स्वास्थ्य, भलाई और खेलः युवाओं के लिए एजेंडा' अंतिम महत्वपूर्ण विषय है

उनके समाधानों को सुने

भारत इस वर्ष के अंत में जी20 प्रेसीडेंसी के अंतर्गत यूथ20 (वाई20) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यह विश्वभर के युवाओं के लिए अपने दृष्टिकोण, मूल्यों और विचारों को व्यक्त करने का अवसर है, जिनको जी20 के नेताओं के साथ साझा किया जाएगा। वाई20 शिखर सम्मेलन दुनिया भर के युवाओं की मेजबानी करेगा, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सुना जाएगा, जो भविष्य का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।

शिखर सम्मेलन के पांच प्रमुख विषयों को मोर डिजिटल, विघटनकारी, मांग-संचालित दुनिया जैसे मापदंड़ों को ध्यान में रखकर चुना गया था। पहला विषय— 'फ्यूचर ऑफ वर्कः इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड 21वीं सेंचुरी स्किल्स' रहेगा ।

जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम चक्र, बदलते फसल चक्र और प्राकृतिक आपदाएं, जैसाकि तुर्की और सीरिया ने देखा है, दूसरे विषय को गंभीर बनाते है- 'जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी', जो 'सतत विकास को जीवनशैली का एक हिस्सा बनाने' पर ध्यान केंद्रित करेगा।

बुद्ध की भूमि ने हमें ध्यान और आध्यात्मिकता सिखाई है। अपने 2014 यूएनजीए के भाषण में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा पेश किये गये योग दिवस के प्रस्ताव को 177 सदस्य राष्ट्रों द्वारा समर्थित किया गया था। दुनिया ने 21 जून, 2015 को अपना पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। 'स्वास्थ्य, भलाई और खेलः युवाओं के लिए एजेंडा' अंतिम महत्वपूर्ण विषय है।

विचारों का आदान-प्रदान

लगभग 21 विदेशी प्रतिनिधियों और 200 भारतीयों ने गुवाहाटी, असम में हाल ही में वाई20 की आरंभिक बैठक में भाग लिया, जिसमें छात्र, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध संस्थानों के विभिन्न विभागों के प्रमुख, उद्योग विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। पैनलिस्टों में सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सतीश

दुआ के साथ दो आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही बिपुल कलिता और बिनल वारी शामिल थे। वैज्ञानिक, उद्यमी, खिलाड़ी, डॉक्टर, उद्योगपति, सलाहकार इंजीनियर, संस्थापक, प्रोफेसर, सभी कॉन्क्लेव का हिस्सा थे। मैंने आईआईटी गुवाहाटी में सभी प्रतिनिधियों के साथ एक युवा संवाद भी आयोजित किया। आयोजन में असम के 36 कॉलेजों के 10,000 युवाओं ने सेमिनार, वाद-विवाद, कार्यशालाओं और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

इस जटिल दुनिया में 'वसुधैव कुटुम्बकम' का विशेष महत्व है। भारतीय लोकाचार युवाओं को वैश्विक भलाई के लिए व्यक्तिगत हितों से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो एक अधिक न्यायसंगत, टिकाऊ, समावेशी, प्रगतिशील और शांतिपूर्ण दुनिया को स्थापित करता हैं। स्वैच्छिक कार्यों से लेकर दयालुता का भाव पैदा करने को लेकर युवाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालता हैं। यह समय व्यक्तिगत आकांक्षाओं से परे जाकर 'नए भारत' के साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का है।

प्रत्येक दिन आशावादी, उत्साहित और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते युवाओं के लिए अवसर लेकर आता है। हमारा युवा परिवर्तन लाने और अमृत काल के लिए नए विचारों को विकसित करने के लिए हमारी पूंजी है।

भारत का युवा एक ऐसी दुनिया में आशा और सद्भावना को स्थापित करता है, जो अक्सर अनिश्चितता को महसूस करती है। हमारे युवा इस बात को पुष्ट करते हैं कि साहस, निरंतरता, प्रतिबद्धता और सहयोग से कुछ भी संभव है। युवा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानवता का भविष्य युवाओं के हाथों में है।

रूस-यूक्रेन युद्ध को देखते हुए, भारत 'शांति निर्माण और सुलह' की पुरजोर वकालत करता है, एक अन्य विषय, जिसमें 'बिना युद्ध के युग की शुरुआत' पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारी सेना शांति अभियानों में योगदान देने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी है। भारत के लगभग 6,700 सैनिक और पुलिसकर्मी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शांति मिशनों पर हैं।

राजनीतिक युवा इकाई, नागरिक समूह और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ भारत का सहभागी शासन यह सुनिश्चित करता है कि युवाओं की बात को हर स्तर पर सुना जाए, जो चौथे विषय— 'साझा भविष्यः लोकतंत्र और शासन में युवा' को परिलक्षित करता है। ■

(लेखक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का किया उद्घाटन

भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच दूसरी सीमा-पार ऊर्जा पाइपलाइन है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने 18 मार्च को संयुक्त रूप से भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन (आईबीएफपी) का वर्चुअल मोड में उद्घाटन किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सितंबर, 2018 में इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला रखी थी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड 2015 से बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति कर रही है। यह भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच दूसरी सीमा-पार ऊर्जा पाइपलाइन है।

बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग भारत-बांग्लादेश संबंधों की पहचान बन गया है। आईबीएफपी भारत और बांग्लादेश के बीच 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) को बांग्लादेश तक पहुंचाने की क्षमता वाली पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। बांग्लादेश के साथ बेहतर संपर्क दोनों पक्षों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा।

बांग्लादेश भारत का अग्रणी विकास साझेदार है और इस क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार भी है। मैत्री पाइपलाइन के संचालन से दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में मौजूदा सहयोग बढ़ेगा और बांग्लादेश में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र का विकास होगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परियोजना पर निरंतर मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना को धन्यवाद दिया और दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए उनके साथ मिलकर निरंतर काम करने की इच्छा व्यक्त की। ■

'श्री अन्न'— किसानों के लिए वरदान

राजकुमार चाहर

मानव जाति के अस्तित्व में आने पर जो पहला अनाज उगाया गया था, वह संभवतः बाजरा या 'श्री अन्न' था। अपने 2023-24 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बाजरा या मोटे अनाज को 'श्री अन्न' कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल के साथ वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में नामित किया गया है। भारत के नेतृत्व में पूरा विश्व अब 'वर्ष 2023' को 'बाजरा वर्ष' के रूप में मना रहा है। भारत में इसकी औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 मार्च को नई दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में की और अब दुनिया भर में 'श्री अन्न' का प्रचार किया जा रहा है।

इसी प्रकार, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष (IYM)- 2023 के माध्यम से मिलेट के उत्पादन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में केंद्र सरकार 'श्री अन्न' को लोकप्रिय बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सांसदों के लिए लंच का आयोजन हो या दिल्ली में जी-20 की बैठक, इन सभी आयोजनों में अब 'श्री अन्न' व्यंजन प्रमुखता से परोसे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त फूड फेस्टिवल हो या कॉन्क्लेव, श्री अन्न के प्रति विदेशियों को आकर्षित करने और इसके उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।

'बाजरा वर्ष' के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा राष्ट्रीय किसान मोर्चा देश भर में विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियों और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। साथ ही, मोटे अनाज के प्रचार, प्रसार और खपत को बढ़ाने के लिए देश के हर छोटे किसान को 'श्री अन्न' के प्रति जागरूक कर रहा है।

भारत 'श्री अन्न' का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। वर्तमान में हमारे देश से सबसे ज्यादा बाजरा, रागी, कनेरी, ज्वार और कुट्टू एक्सपोर्ट किया जाता है। हम इन्हें अमेरिका, यूएई, ब्रिटेन, नेपाल, सऊदी अरब, यमन, लीबिया, ट्यूनीशिया, ओमान और मिस्र सप्लाई करते हैं।

भारत 'श्री अन्न' का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। वर्तमान में हमारे देश से सबसे ज्यादा बाजरा, रागी, कनेरी, ज्वार और कुट्टू एक्सपोर्ट किया जाता है। हम इन्हें अमेरिका, यूएई, ब्रिटेन, नेपाल, सऊदी अरब, यमन, लीबिया, ट्यूनीशिया, ओमान और मिस्र सप्लाई करते हैं

लेकिन, मिलेट की कौन सी विशेषताएं इसे 'सुपर फूड' या 'श्री अन्न' बनाती हैं और यह सभी के लिए फायदेमंद क्यों है, यह सवाल है?

श्री अन्न या मिलेट्स क्या है

सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान 'श्री अन्न' की खपत को लेकर कई साक्ष्य बताते हैं कि यह भारत में पैदा की जाने वाली पहली फसलों में से एक थी। इसे गरीबों का अनाज भी कहा जाता है। मिलेट्स सेहत के लिए भी काफी अच्छा होता है। मिलेट्स सिर्फ प्रोटीन और फाइबर ही नहीं देते, बल्कि खाने वाले को शरीर में उत्पन्न हो रहे रोगों का निदान भी करते हैं।

श्री अन्न सुपर फूड क्यों है

दरअसल श्री अन्न में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। इसके साथ ही बीटा-कैरोटीन, विटामिन-बी6, फोलिक एसिड, पोटैशियम, मैग्नीशियम, जस्ता आदि से ये अनाज भरपूर होते हैं। इसमें फाइबर यानी रेशा मौजूद होता है, जिससे पाचन दुरुस्त होता है। इस तरह इसको खाने वाले को कब्ज की समस्या नहीं होती। इनका सेवन करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है। 'श्री अन्न' डायबिटीज तथा दिल के रोगियों के लिए भी उत्तम माना जाता है। इन्हीं सब कारणों से श्री अन्न को सुपरफूड भी कहा जाता है।

श्री अन्न में क्या-क्या शामिल है

- **ज्वार:** यह ग्लूटेन फ्री और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। डायबिटीज के मरीजों के लिए बढ़िया भोजन है।
- **बाजरा:** इसमें विटामिन बी6, फॉलिक एसिड मौजूद है। ये खून की कमी को दूर करता है।
- **रागी:** यह नेचुरल कैल्शियम का स्रोत है। बढ़ते बच्चे और बुजुर्गों की हड्डी मजबूत करने में मदद करता है
- **सांवा या सामा:** फाइबर और आयरन से भरपूर है। एसिडिटी, कब्जियत और खून की कमी को दूर करता है।
- **कंगनी:** ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। बीपी और बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है।
- **कोदो:** यह भी फाइबर से भरपूर है। घेंघा रोग, रुसी की समस्या पर से संबंधित बीमारी और बवासीर में फायदेमंद है।
- **कुटकी:** ये एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम हेल्दी हार्ट और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है।
- **कुट्टू:** ये अस्थमा के रोगियों के लिए

फायदेमंद है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड बाल झड़ने से रोकता है।

इसकी खेती करना भी आसान

पीएम मोदी भी चाहते हैं कि श्री अन्न या भारत मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बने और अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को 'जन आंदोलन' का रूप दिया जाए। बेशक, भारत दुनिया को मोटा अनाज के लाभ बताने-समझाने में अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे देश में एशिया का लगभग 80 प्रतिशत और विश्व का 20 प्रतिशत मोटा अनाज पैदा होता है। मोटे अनाज की खेती कम लागत और कम पानी में हो जाती है। इस फसल में रोग भी कम लगते हैं जिससे कीटनाशकों का उपयोग भी न के बराबर ही होता है। चूंकि, यह असिंचित भूमि पर आसानी से हो सकता है, अतः यदि मांग बढ़ेगी तो भारत में इसकी पैदावार कई गुना बढाई जा सकती है।

किसानों की भी आय बढ़ेगी

'श्री अन्न' या मोटे अनाज की खेती में कम मेहनत लगती है और पानी की भी कम ही जरूरत होती है। यह ऐसा अन्न है जो बिना सिंचाई और बिना खाद के पैदा किया जा सकता है। भारत की कुल कृषि भूमि में मात्र 25-30 फीसद ही सिंचित या अर्धसिंचित है। जब 'श्री अन्न' की मांग बढ़ेगी तो बाजार में इनका दाम बढ़ेगा तभी असंचित भूमि वाले गरीब किसानों की आय भी बढेगी।

मिलेट फसल वर्षा आधारित होता है, जिसे कम खर्च व कम पानी में उगा सकते हैं। गरीब किसान बंजर धरती में इसका उत्पादन कर सकते हैं। मिलेट का उपयोग जितना बढ़ेगा, भोजन में उतने पोषक तत्व मिलेंगे, जिसका फायदा लोगों को होगा। मिलेट का उपयोग दुनिया में बढ़ेगा तो प्रोसेसिंग बढ़ेगी, निर्यात बढ़ेगा, जिसका लाभ छोटे किसानों को होगा और उनकी माली हालत सुधारने में सफलता मिलेगी। यह मिलेट ईयर इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।

मिलेट की खपत को बढ़ावा

प्रधानमंत्री के निर्देशन में जी-20 की बैठकों के माध्यम से भी मिलेट के प्रचार-प्रसार की योजना तैयार की गई है। जी-20 के सभी कार्यक्रमों में भोजन में मिलेट को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि जब ये लोग अपने देश लौटे तो यहां से भोजन का अच्छा स्वाद लेकर जाएं और दुनियाभर में भारतीय 'श्री अन्न' को नई पहचान मिलें। इसका लाभ हमारे किसानों व देश को मिलेगा।

देश में इस पर शोध बढ़ाने के लिए हरियाणा, हैदराबाद और बेंगलुरु में तीन राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से काफी काम किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में लगभग 2000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश मिलेट से संबंधित हैं। हमारे देश से 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कृषि उत्पाद का निर्यात किया गया, जिसमें से अधिकांश जैविक उत्पाद या मिलेट हैं।

'श्री अन्न' (मिलेट) आज की जरूरत है क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर है। ये पौष्टिक अनाज खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत बाजरा का एक प्रमुख उत्पादक है, फिर भी दैनिक आहार के मामले में हमारी थाली से मिलेट गायब है। वर्तमान परिवेश में चाहे घर में हो या बाहर, हमें भोजन तो मिलता है, लेकिन उसमें आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों की कमी होती है। हमें अपने भोजन की थाली में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता है, इसके लिए थाली में 'श्री अन्न' का होना आवश्यक है। ■

(लेखक भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत का कुल निर्यात 750 अरब डॉलर के अब तक के सबसे उच्च स्तर को पार

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 28 मार्च को बताया कि भारत का कुल निर्यात, जिसमें सेवाओं और व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात शामिल है, आज 750 अरब डॉलर को पार कर गया। यह अब तक का सर्वकालिक उच्च स्तर है और 750 अरब डॉलर की यह उपलब्धि आजादी के 75वें वर्ष में हासिल हुई है, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।

श्री गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे निर्यात 2020-21 के 500 अरब डॉलर से बढ़कर बेहद चुनौतीपूर्ण समय में इस आंकड़े तक पहुंचा है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में एसोचैम के वार्षिक सत्र 2023: 'भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती' में दिए अपने मुख्य भाषण में कहा कि माल और सेवा दोनों क्षेत्रों में मजबूत प्रगति दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि पूरी दुनिया में मंदी है, अधिकांश विकसित देशों के लिए मुद्रास्फीति अब तक के उच्चतम स्तर पर है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं और बाकी दुनिया में निराशा की भावना है, भारत का प्रदर्शन हमें गर्व से भर देता है। ■

भारत और जापान ने रक्षा उपकरण, तकनीकी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर की बातचीत

भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी दोनों देशों के साझा लोकतान्त्रिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय पटल पर कानून के शासन के सम्मान पर आधारित है

जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर 20 मार्च को नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और विभिन्न महत्वपूर्ण वैश्विक, क्षेत्रीय व आपसी मुद्दों पर बातचीत की। उल्लेखनीय है कि जापान उन बहुत कम देशों में से एक है, जिसके साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन की परंपरा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2014 में भारत के निकटतम पड़ोसी देशों के बाद जापान की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा की थी।

दोनों देशों की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण पिछले कुछ वर्षों में आपसी संबंधों व साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जिसमें राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक हितों समेत सभी आयाम शामिल हैं। भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, क़ानून का शासन, हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

संयुक्त प्रेस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत-जापान संबंधों के प्रति उनकी सकारात्मकता और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। इसलिए, आज की उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग की गति बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी।

इस साल भारत जी20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान जी7 की

श्री मोदी ने कहा कि आज की हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत जी20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान जी7 की। इसलिए, अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की जी20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। हमारी जी20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ 'ग्लोबल साउथ' की प्राथमिकताओं को आवाज़ देना है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसीलिए हमने यह पहल ली है।

उन्होंने कहा कि भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी हमारे साझा लोकतान्त्रिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय पटल पर कानून के शासन के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शान्ति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है।

श्री मोदी ने कहा कि आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान-प्रदान किया। सेमीकन्डक्टर और अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में विश्वस्त सप्लाई चेन के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई। पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन, यानी तीन लाख बीस हजार करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है।

उन्होंने कहा कि 2019 में हमने भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी (India-Japan Industrial Competitiveness Partnership) की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई, टेक्सटाइल, मशीनरी और इस्पात जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धात्मकता (competitiveness) बढ़ा रहे हैं। आज हमने इस भागीदारी की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहें है और इसके लिए हमने ''कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फूजी' नाम का थीम चुना है।

श्री मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री किशिदा ने मुझे मई महीने में हिरोशिमा मे होने वाली जी7 लीडर्स समिट के लिए निमंत्रण दिया। इसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसके कुछ महीनों बाद सितम्बर में जी20 लीडर्स समिट के लिए मुझे प्रधानमंत्री किशिदा का फिर से भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा। ■

प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा

काशी के विकास की आज पूरे देश और दुनिया में चर्चा: नरेन्द्र मोदी

पिछले नौ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी के परिदृश्य को बदलने और इस शहर एवं इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए इस वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में 1780 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक पैसेंजर रोपवे का शिलान्यास किया। इस परियोजना की लागत लगभग 645 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पांच स्टेशनों वाली यह रोपवे प्रणाली 3.75 किलोमीटर लंबी होगी। इससे पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और वाराणसी के निवासियों का आवागमन सुविधाजनक होगा। प्रधानमंत्री ने 'नमामि गंगे योजना' के तहत भगवानपुर में 55 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया। श्री मोदी ने सेवापुरी के इस रवर गांव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 'जल जीवन मिशन' के तहत 19 पेयजल योजनाओं का लोकार्पण किया। ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को और मजबूत करने से उद्देश्य से श्री मोदी ने इस मिशन के तहत 59 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास भी किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मार्च को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नवरात्र का पुण्य समय है, आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूं। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आज बनारस की सुख-समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें पीने के पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा जी की साफ-सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा, खेल सुविधा ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है, वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। आप याद कीजिए, 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था, तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको आशंकाएं थीं। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन काशी के लोगों ने आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया है।

आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों का दर्शन

श्री मोदी ने कहा कि आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मुझे देश-विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्रमुग्ध हैं। लोग गंगा घाट पर हुए काम से प्रभावित हैं। हाल ही में जब दुनिया का सबसे लंबा रिवरक्रूज हमारी काशी से चला, उसकी भी बहुत चर्चा हुई है। एक समय था, जब गंगा जी में इसके बारे में सोचना भी असंभव था, लेकिन बनारस के लोगों ने ये भी करके दिखाया। आप लोगों के इन्हीं प्रयासों की वजह से एक साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी आए।

उन्होंने कहा कि 8-9 वर्षों के विकास कार्यों के बाद जिस तेजी से बनारस का विकास हो रहा है, अब उसे नई गति देने का भी समय आ गया है। आज यहां टूरिज्म से जुड़े शहर के सुंदरीकरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रोड हो, पुल हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के तमाम नए साधनों ने काशी आना-जाना बहुत आसान कर दिया है। ■

अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग प्रणाली में दबाव के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तैयारियों की हुई समीक्षा

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विभिन्न वित्तीय मानकों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रदर्शन और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप में कुछ अंतरराष्ट्रीय बैंकों की विफलता से उत्पन्न वर्तमान वैश्विक वित्तीय परिदृश्य के आलोक में पीएसबी की सहनीयता की समीक्षा करने के लिए 25 मार्च को आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड़, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव डॉ. विवेक जोशी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक के दौरान सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक की विफलता तथा क्रेडिट सुइस में संकट के मुद्दों समेत वर्तमान वैश्विक परिदृश्य पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ खुली चर्चा हुई। श्रीमती सीतारमण ने लघु और दीर्घकालिक, दोनों दृष्टिकोणों से इस उभरते हुए और तात्कालिक तौर पर बाहरी वैश्विक वित्तीय दबाव के सन्दर्भ में पीएसबी के जोखिम की समीक्षा की।

पीएसबी की समीक्षा बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने जोखिम प्रबंधन, जमाराशि के विविधीकरण एवं परिसंपत्तियों के आधार पर ध्यान केन्द्रित करके नियामक ढांचे के अनुपालन के जरिए सम्यक तत्परता के साथ तैयारी करने पर जोर दिया।

पीएसबी के एमडी और सीईओ ने वित्त मंत्री को इस तथ्य से अवगत कराया कि वे कॉरपोरेट प्रशासन की उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को अपनाते हैं, नियामक मानदंडों का अनुपालन करते हैं, विवेकपूर्ण तरलता प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं और मजबूत परिसंपत्ति-देयता एवं जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। इसके अलावा, पीएसबी द्वारा श्रीमती सीतारमण को यह भी बताया गया कि वे वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर सतर्क हैं और किसी भी संभावित वित्तीय झटके से खुद को बचाने के लिए हरसंभव कदम उठा रहे हैं। सभी प्रमुख वित्तीय मापदंड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूत वित्तीय सेहत के साथ-साथ उनकी स्थिर और सुदृढ़ स्थिति का संकेत देते हैं। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

12 मार्च, 2023 को मांड्या (कर्नाटक) आगमन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भव्य स्वागत

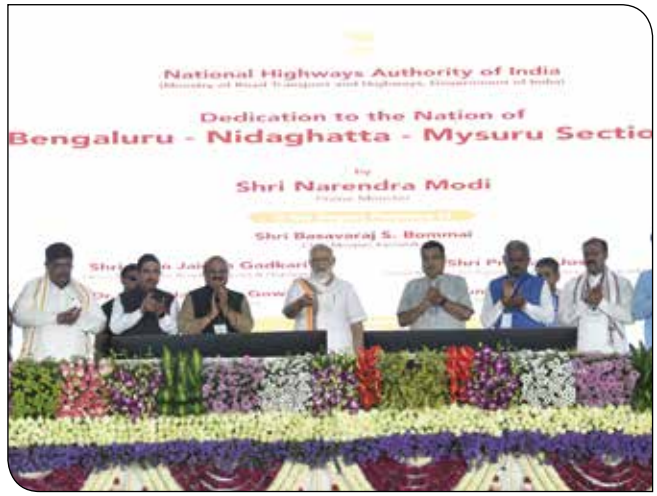

मांड्या (कर्नाटक) में 12 मार्च, 2023 को प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

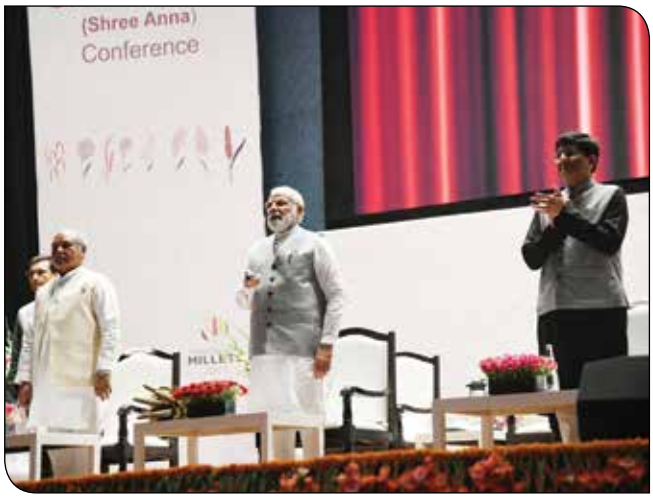

नई दिल्ली में सुब्रमण्यम हॉल (पूसा) में 18 मार्च, 2023 को ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

राष्ट्रपति भवन (नई दिल्ली) में 10 मार्च, 2023 को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीस का स्वागत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

हैदराबाद हाउस (नई दिल्ली) में 20 मार्च, 2023 को जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भारत–बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का 18 मार्च, 2023 को संयुक्त रूप से उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh

@KamalSandesh

kamal.sandesh

KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह

डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**

36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953

डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23

Licence to Post without Prepayment

Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह